माला, खंड २६, अंक ४१ शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४/ १४ चैत्र, १८८६ (शक)

Series, Vol. XXIX No. 41. Saturday, April 11, 1964/Chaitra 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

Preservation Unit
21-5-97
Fumigated
On 19.12.98
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sahbha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक ४८—शनिवार, ११ अप्रैल, १९६४/२२ चैत्र, १८८६ (शक)

विषय	पृष्ठ
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न) .	३६७९—८७
सभा पटल पर रखा गया पत्र	३६८७
सभा का कार्य	३६८७—८३
अनुदानों की मांगें	३६८३—३६९०
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	३६८३—३६९०
श्री कु० चं० शर्मा	३६८३—८४
श्री रवीन्द्र बर्मा	३६८४—८६
श्री कृपालानी	३६८६—८८
श्री कृष्ण मेनन	३६८८—९३
श्री उमानाथ	३६९३—९५
श्री उ० मू० त्रिवेदी	३६९५—९७
श्री अन्सार हपवानी	३६९७—९८
श्री मनोहरन	३६९८—९९
श्री कु० शिवप्रघासन	३६९९—३७००
श्री जोकीम अल्वा	३७००—०२
श्री बिशनचन्द्र सेठ	३७०२—०३
श्री इकबाल सिंह	३७०३—०४
डा० राम मनोहर लोहिया	३७०४—०६
श्रीमती सावित्री निगम	३७०६—०७
श्री लाल बहादुर शास्त्री	३७०७—१०

CONTENTS

No. 48.—Saturday, April 11, 1964/Chaitra 22, 1886 (Saka)

Subject	Pages
Re: Calling Attention Notices and Adjournment Motions (Query)	3679–81
Paper laid on the Table	3681
Business of the House	3681–83
Demands for Grants	3683—3710
Ministry of External Affairs	3683—3710
Shri K. C. Sharma	3683–84
Shri Ravindra Varma	3684–86
Shri J. B. Kripalani	3686–88
Shri Krishna Menon	3688–93
Shri Umanath	3693–95
Shri U. M. Trivedi	3695–97
Shri Ansar Harvani	3697–98
Shri Manoharan	3698–99
Shri K. Sivappraghassan	3699—3700
Shri Loachim Alva	3700–02
Shri Bishanchander Seth	3702–03
Shri Iqbal Singh	3703–04
Dr. Ram Manohar Lohia	3704–06
Shrimati Savitri Nigam	3606–07
Shri Lal Bahadur Shastri	3707–10

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, ११ अप्रैल, १९६४/२२ चैत्र, १८८६ (शक)

Saturday, April 11, 1964/Chaitra 22, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

ध्यान दिलाने वाली सचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICES AND ADJOURNMENT MOTIONS QUERY

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बंगाल से काफी महिलायें आई हुई हैं और वे शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हैं । अतः संबंधित मंत्री अथवा संसद-कार्य मंत्री को उनसे मिलना चाहिये और उनको आश्वासन देना चाहिये कि सरकार शरणार्थियों की मुसीबतों को दूर करने के लिये हर संभव प्रयत्न करेगी और यह भी प्रयत्न करेगी कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न हों ।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : यदि अध्यक्ष महोदय भी उनसे मिलने की कृपा करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I have tabled a calling attention notice on this matter. Government should attend to this matter and tell us what they are going to do. I would request you to consider it sympathetically as it is an important issue.

श्री बड़े (खारगोन) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है परन्तु समाचार-पत्रों में यह दिया हुआ है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह निर्णय कर लिया है कि दो महीने तक न्यायाधिकरण का कार्य स्थगित रहेगा । यह न्यायाधिकरण इस प्रश्न की जांच कर रहा है कि अवैध रूप से

प्रवेश करने वालों को बाहर निकाला जाये अथवा नहीं । हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने संसद् को विश्वास में लेने से पहले ऐसा निर्णय क्यों किया ?

श्री त्यागी (देहरादून) : प्रत्येक प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये । मेरे माननीय मित्र को ध्यान दिलाने वाली सूचना देनी चाहिये । तभी संबंधित मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहा जा सकता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दे रखी है, अतः मुझे आशा थी कि उसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा सुझाव यह है कि कोई माननीय मंत्री उन महिलाओं से जा कर मिल लें क्योंकि इस प्रदर्शन का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। बम्बई में हुई हड़ताल के बारे में दिये गये स्थगन प्रस्ताव अथवा हिन्द महासागर में सातवें बेड़े के प्रवेश के बारे में दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से इनके बारे में कोई वक्तव्य दिया जायेगा ।

Shri Kachhavaiya (Dewas) : I request you to accept my adjournment motion because it raises an important issue.

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : मैं श्री नाथ पाई के सुझाव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि माननीय संसद्कार्य मंत्री प्रदर्शनकारियों से भेंट करें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह आशा नहीं थी कि प्रमुख दलों के नेता इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा डालेंगे । आज प्रश्न-काल नहीं था । अतः मेरे लिये इन स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में एकदम कुछ कहना संभव नहीं था, क्योंकि इनकी सूचना मुझे अभी भी प्राप्त हो रही है । मेरी राय में हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्योंकि आपने सभा पटल पर पत्र रखने का आदेश दिया था अतः हमने समझा कि उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है नियमों के अनुसार ऐसा करना चाहे उचित नही हो, फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय को इसलिए उठाना चाहा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं था अन्यथा प्रत्येक सम्बन्धित माननीय सदस्य को सूचना भेज दी गई होती ।

श्री स० मो० बनर्जी : सामान्य प्रक्रिया यह है कि ध्यान दिलाने वाली सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव को सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से पहले लिया जाता है । अतः जब आपने सभा पटल पर पत्र रखने के लिये कहा तो हमें यह सन्देह हुआ कि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक ही समझा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जिस दिन कोई प्रश्न काल न हो, क्या उस दिन भी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों आदि को देने के बारे में वही नियम लागू होगा या उसमें कोई रूपभेद किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वही नियम लागू होगा परन्तु मेरे सभा में आने से पहले प्रत्येक सदस्य को सूचना दे दी जायेगी ।

मंत्री महोदय को, जो कुछ यहां पर कहा गया है, उस पर विचार करके उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक २६ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१९ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (सातवां संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—२६९१ / ६४]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं सभा को सूचित करता हूं कि १३ अप्रैल, १९६४ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(१) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान ।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

(३) वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

(४) बुधवार १५ अप्रैल, १९६४ को ५ म० प० बजे अनुदानों की शेष मांगें सभा के सामने मतदान के लिए रखी जायेंगी ।

(५) वित्त विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पास करना**) ।

(६) कम्पनीज़ (लाभ) अतिकर विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पास करना**) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सत्र १ मई, के बाद भी जारी रहेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे खेद है कि गृह-कार्य मंत्री के किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सका । विभिन्न मंत्रालयों ने २६ विधेयकों को प्राथमिकता दी है जिन्हें पास करने के लिये मई का पूरा मास चाहिये । अतः उन सभी मंत्रालयों तथा मंत्रियों की इस मामले पर विचार करने के लिये सोमवार या मंगलवार को एक बैठक होगी । हम चाहते हैं कि सरकारी कार्य मई के पहले सप्ताह तक निपटा दिया जाये ? परन्तु कुछ विधेयकों तथा अन्य कार्यों का सभा के वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पहले निपटाया जाना जरूरी है । मैं सभा को आगामी शुक्रवार तक निश्चित रूप से इस बारे में सूचना दे दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि संकटकाल की स्थिति में कुछ सुधार हो गया है, इसलिये सदस्यों को पांच से अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । पहले हम एक चक्र पूरा करते हैं और फिर वह दोहराया जाता है । इस प्रकार २० प्रश्नों की सूची ही हम बहुत कम बार पूरी कर पाये हैं । अतः शेष प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों के रूप में कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु कुछ मंत्रालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अस्वीकार हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे मंत्रालयों की संख्या अधिक हो अथवा कम, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुभव है कि प्रश्नकाल में २० से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): संसद कार्य मंत्री ने कहा है कि १५ अप्रैल को ५ बजे शाम को शेष मांगें सभा में मतदान के लिये रखी जायेंगी । अतः मेरा निवेदन है कि यह समय बढ़ाया जाये ताकि मांगों के लिये अधिक समय उपलब्ध हो सके । जहां तक नियम २०८ का सम्बंध है, हमें इस नियम का इतनी सख्ती से पालन नहीं करना चाहिये कि केवल निर्धारित दिन के ५ बजे शाम को ही इन मांगों पर मतदान होगा । यदि यह एक नियम विरुद्ध कार्य नहीं है तो हम मांगों पर चर्चा का समय ६–३० या ७ म० प० बजे तक बढ़ा सकते हैं । मैंने इस नियम में संशोधन करने की सूचना भी देखी है । मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि ऐसा संशोधन करना आवश्यक नहीं है और उस दिन यह प्रस्ताव किया जा सकता है कि इस नियम को निलम्बित किया जाये । यदि आप का ऐसा विचार है तो मैं उस दिन इसी आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा और मुझे आशा है कि सभा उसे स्वीकार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि सभा ५–३० म०प० बजे के बाद बैठने के लिये तैयार नहीं है । यदि नियम को निलम्बित भी कर दिया जाये, तब भी हम ५.३० म० प० बजे तक ही बैठ सकते हैं ।

जहां तक नियम में संशोधन करने सम्बंधी सूचना का प्रश्न है, मुझे वह सूचना मिल गई है और उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की मांगों को छोड़ कर, शेष मांगों पर चर्चा की जा सकेगी अतः क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती जिससे सभा अधिक समय तक बैठने के लिये सहमत हो जाये ताकि उन मांगों पर भी चर्चा की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस बारे में मुझ से तथा संसद मंत्री से विचार विमर्श करें । इस पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री हरि विष्णु कामत : वित्त विधेयक के लिये १७½ घंटे निर्धारित किये गये हैं । यदि हम आगामी गुरूवार को २ म० प० बजे या ३ म० प० बजे वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ करें तब भी २१ अप्रैल तक १७½ घंटे पर हो जायेंगे । इसलिये गुरूवार को कुछ समय के लिये किसी मंत्रालय तथा योजना आयोग की मांगों पर चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : जब इन पर चर्चा आरम्भ होगी, तब देखा जायेगा ।

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—**Contd.**

वैदेशिक कार्य मंत्रालय---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों तथा उन पर पेश किये गये कटौती प्रस्तावों पर आगे चर्चा तथा मतदान होगा ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : विश्व शांति का होना अनिवार्य है, परन्तु विश्व शांति एक स्वर्ण युग नहीं है, इससे झगड़े समाप्त नहीं हो जाते । फिर भी विवादों को हल करने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । विश्व शांति बनाये रखने के लिये नैतिक प्रयत्न करना जरूरी है । इसीलिये हम तटस्थता, सह अस्तित्व और पंचशील की नीति का अनुसरण करते आ रहे हैं । कोरिया तथा इन्डो-चाइना के विवादों को सुलझाने में भारत ने काफी योगदान दिया है । एशिया के देशों की स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता बनाये रखने में हमने पूरा योगदान दिया है ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति बनाये रखने का एकमात्र उपाय यह था कि भारत तथा संयुक्त जर्मनी तटस्थ रहें । भारत तटस्थ ही नहीं रहा अपितु उसने सह-अस्तित्व तथा पारस्परिक सहयोग पर पूरा जोर दिया । उसका परिणाम यह हुआ है कि विश्व पर अब दो गुटों का ही प्रभुत्व नहीं बना हुआ है अपितु जर्मनी, इटली, चीन, भारत तथा जापान भी विश्व के मामलों में अपना अपना योगदान दे रहे हैं ।

यह बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि चीन ने हमें पराजित किया है और हमारा अपमान किया है । परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियां भी काफी सीमा तक इसके लिये उत्तरदायी थीं । चीन की सेना ने पर्वतों से भारत पर आक्रमण किया । ऊपर से नीचे की सेना पर हमला करने वाला सदैव अच्छी स्थिति में होता है । पर्वत की नीची घाटियों से लड़ने वाली सेना के लिये पर्वत पर से लड़ रही सेना पर हमला करना तथा उस पर विजय पाना कठिन है । परन्तु यदि शत्रु कुछ और आगे बढ़ जाता तो उसकी संचार व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता था और आखिर में उसे पराजित ही होना पड़ता क्योंकि भारतीय जवान हिम्मत हारने वाले नहीं हैं । १८१२ में नेपोलियन के समय तथा १९४० में हिटलर के समय में भी दुश्मन की फौजें काफी अन्दर तक घुस आई थी परन्तु आखिर में रूस की ही विजय हुई थी क्योंकि रूसी सेना ने हिम्मत नहीं हारी ।

एक लड़ाई से किसी युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता। इतिहास साक्षी है किसी देश के लक्ष्य से उसका भाग्य निर्णय होता है। कई बड़े देश कई बार हारे हैं किन्तु वे आज पहले से अधिक महान हैं। अतः मेरे माननीय मित्र का विचार बचगाना है।

जब दो महान राष्ट्रों का मुकाबला होता है तो अनिवार्यतः जटिल मामलों में विलम्ब होता हो है। आजकल विवाद का हल परस्पर वार्ता या सहतटस्थता से हीं होता है और युद्ध तो अन्तिम उपाय होता है जिसे कोई भी विवेकशील राजनीतिज्ञ अपनाने के लिये तैयार नहीं होता।

विदेश नीति के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। पहले तो यह वस्तुगत नियमों और मानव प्रकृति से नियंत्रित होती है। प्राचीन दार्शनिक विचारधाराओं में तो परिवर्तन होता रहा है किन्तु मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ।

दूसरा सिद्धांत है राष्ट्रहित जिसकी व्याख्या शत्रुओं के विरुद्ध शक्ति द्वारा की जाती है। तीसरा सिद्धांत यह है कि राजनैतिक यथार्थवाद के कारण शक्ति के आधार पर हित की व्याख्या नहीं की जा सकती। श्री नाथ पाई वास्तविक के मूल नेहरू को नेपोलियन या सीज़र बनने के लिए कहते हैं जो आधुनिक परिस्थितियों में संभव नहीं। श्री नेहरू इतिहासकार, दार्शनिक और भविष्य निर्माता प्रमाणित हुए हैं।

चीन के साथ विवाद के सम्बंध में मुझे विदित निवेदन करना है कि न तो चीन हमें हरा सकता है और न ही हम उसे हरा सकते हैं। अतः एक समय आयेगा जब हम सब एशिया के लोग परस्पर मिल जायेंगे।

मनुष्य की भूल ने पाकिस्तान को हम से अलग कर दिया है और पाकिस्तान में भी आधुनिक विवेकशीलता का प्रादुर्भाव होगा और फिर वहां ऐसी घटनाएं नहीं होंगी जो आज हो रही हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : इन तीनों दिनों की चर्चा में यह बात सराहनीय रही कि जो सदस्य गुटों से अलग रहने की नीति का सदा विरोध करते रहे हैं उन्होंने भी इसकी अवेहलना नहीं की। हमने इस नीति को इसलिए अपनाया है कि हम स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने आपको उपनिवेशवाद और जातिवाद का साथी नहीं बनाना चाहते।

हम इसलिए भी गुटों से अलग रहने की नीति का पालन कर रहे हैं कि हम विरोधी गुटों की आर्थिक प्रणालियों में से किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहते। जो देश इस नीति को संदेह की दृष्टि से देखा करते थे उन्होंने भी इसके मूल्य को स्वीकार कर लिया है।

किन्तु हमारी नीति की कुछ धारणाओं पर हाल ही में आपत्ति की जाने लगी है। हाल ही घटनाओं के फलस्वरूप इन धारणाओं पर गहरा आघात पहुंचा है अतः हमें अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

पहले तो बहुत से देश हमारे इस नीति को अपनाने के समय तक औपनिवेशिक शासन के अधीन थे और शेष संसार शीत युद्ध में ग्रस्त था। आज चीन सह अस्तित्व के सिद्धांत का विरोध कर रहा है और फ्रांस भी उसका साथी बन गया है तथा उसके साथ ऐसे व्यापार सम्बंध बना चुका है कि पैट्रोल जैसी युद्ध सामग्री तक उसे बेचने लगा है।

दूसरे हमारा विश्वास था कि यदि हम गुटों से अलग रहें तो अर्द्ध विकसित देशों को आन्तरिक विध्वंश के भले ही खतरा रहे बाहर से कोई देश आक्रमण नहीं करेगा। इस विश्वास पर आपत्ति की जाने लगी है।

हमें अब यह अनुभव हो गया है दाण्डिक संहिता का स्थान नैतिक उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे शत्रु आज इस प्रकार की चालें चल रहे हैं कि कूट नीति को गतिशील बनाना और भी आवश्यक हो गया है। खुल्लम खुल्ला शत्रुता करने वालों के अलावा हमारे सिद्धांतहीन शत्रु भी है जो हमारी सामाओं को हड़प रहे हैं और साथ बार्ता के लिए आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार विश्वास रखते हैं कि हमारे लोगों में सर्वांगीण युद्ध का मंत्र है और वे सीमित युद्ध और वार्ता की चालों से देश के साहस का हनन कर देंगे।

इसका उत्तर यथार्थहीन परमार्थवाद नहीं है। हर राष्ट्र की विदेश नीति आत्म हित की भावना पर आधारित होती है आत्म हित स्वार्थाधित्य नहीं है। अतः हमारी कूटनीति का आधार आत्महित होना चाहिये और दुस्साही शत्रु को रोकना चाहिये। अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाना चाहिये तथा अन्य देशों में प्रचार द्वारा अपने मित्र राष्ट्र बनाने चाहिये।

गत वर्ष और उससे पूर्व इस मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैंने यह कहा था कि चीन और पाकिस्तान ने हमारे देश के विरुद्ध राजनयिक आक्रमण कर दिया है। हमें इस का मुकाबला सरकारों के बीच सम्पर्क द्वारा नहीं बल्कि खुले प्रचार द्वारा करना चाहिये। वास्तव में श्री नाथपाई और श्री खाडिलकर ने यह ठीक ही कहा है कि हमारे मित्र कम हो रहे हैं। यह कहना गलत है कि चीन मित्र विहिन हो गया है। क्या विश्व के साम्यवादी दलों में उसके मित्र नहीं हैं? एशिया और यूरोप में साम्यवादी दलों में विभाजन हो गया है और उनमें पीकिंग के समर्थक गुट भी हैं। शत्रु की शक्ति को कम बना कर आप उसे जीत नहीं सकते। चीन ने अर्द्ध विकसित देशों में नीतिवाद को भड़काया है और रूस पर प्रभुता की भावना का आरोप लगाया है। पाकिस्तान को न केवल चीन बल्कि ऐसे राष्ट्रों का भी समर्थन प्राप्त है जहां वह धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है। आपको विदित है कि हाल ही में पाकिस्तान ने जेरुसलेम के मुफ्ती द्वारा अरब देशों के दौरे का आयोजन किया था जिसमें मुफ्ती ने कश्मीर में आत्म निर्णय पर बल दिया था।

ऐसे शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए हमें कूटनीति को गतिशील बनाना चाहिये। यह मिथ्या गर्व है कि हमारा देश ५००० वर्ष पूर्व महान था। हमें केवल इस आशंका से निष्क्रिय नहीं रहना चाहिये कि कहीं कोई गलती न हो जाए।

अर्द्ध विकसित देशों में एक पक्षीय धारणाएं नहीं हैं अतः यह सोचना गलत है कि हमारी वर्तमान समस्याएं एक सी हैं अतः इन समस्याओं के हल के सम्बंध में उनकी धारणाएं हमारे समान होंगी। वे कुछ आन्तरिक विफलताओं और प्रादेशिक नेतृत्व की आकांक्षा से चीनियों के समान अपनी नीतियों को बना रहेहैं। हम अपने मित्रों और शत्रु के मित्रों को समान दृष्टि से देख कर राष्ट्रों से अधिकाधिक समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री खाडिलकर का कथन है कि अफ्रोएशियाई देशों में हमारी स्थिति इसलिए गिरी है कि हमने उपक्रम करके चीन के साथ निबटारा नहीं किया और उसका साहसपूर्ण सुझाव यह था कि हम लद्दाख देकर चीन से मैकमोहन लाइन स्वीकार करवा लें। किन्तु क्या अर्द्ध विकसित देशों में हमारी स्थिति गिरी है। क्या चीन ने यह चाल इसलिये चली है कि हम विश्व की सहानुभूति को नहीं जगा सकेंगे?

श्री खाडिलकर ने यह भी कहा था कि हमें आत्मसम्मान की दुहाई नहीं देनी चाहिये। किन्तु क्या कोई देश केवल आत्म सम्मान के लिए अपने क्षेत्र की रक्षा करता है ? क्या देश का कुछ ऐसा भाग रखा जा सकता है जिसे कभी भी बलिदान किया जा सके क्या हम आक्रमक से मूल्य देकर शान्ति खरीद सकते हैं ? हम इस प्रकार अपनी दुर्बलता को अपनी श्रेष्ठता नहीं बता सकते।

हमें अफ्रीका और एशिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहिये और उपक्रम करने की नीति से नहीं घबराना चाहिये तथा अपनी कूटनीति को गतिशील बनाना चाहिये।

मैं भी शेख अब्दुल्ला की रिहाई का स्वागत करता हूं किन्तु उससे जो नई समस्याएं उपस्थित हुई हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमने सदा इस बात पर बल दिया है कि काश्मीर का भारत से विलय अपरिवर्तनीय है और कि जनमत संग्रह तभी हो सकता था जब पाकिस्तान अपने अधिकृत क्षेत्र को छोड़ता। किन्तु क्या अब हम उस तर्क को तिलांजली दे रहे है और क्या शेख अब्दुल्ला के कृत्यों से यह विश्वास होता है कि हमारे पक्ष का समर्थन करेगा ? क्या शेख अब्दुल्ला को भारत से अलग होने का प्रचार करने दिया जायगा ? क्या हम पुनः चुनाव होने देंगे और वहां की विधान सभा को कश्मीर के बिलय में परिवर्तन की अनुमति दे देंगे ? मैं ये प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं कर रहा। किन्तु सरकार को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। विदेशों में प्रचार और अन्य देशों के राजदूतों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति पहले की तरह निकृष्ट है। हमारे प्रचार केन्द्र बराबर अनुपात में बटे हुए नहीं और अफ्रीका में बहुत कम है। लेकिन अमरीका में दो है और फ्रांसीसी भाषी क्षेत्रों में एक भी केन्द्र नहीं है।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : हमने विदेश नीति में ऊंचे और सराहनीय सिद्धांतो को अपनाया है। हम शान्ति और निशस्त्रीकरण के समर्थक है। हमने सीमा की नीति में आण्विक युद्ध से बचने को सक्रिय प्रयास किया है। हमारी विदेश नीति विश्व के महान राजनीतिज्ञ के हाथ में है और विदेशों में हमारे राजदूत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। फिर भी क्या कारण है कि हम सब जगह विजित हुए है ? क्या यह कारण है कि हम अपनी अच्छाइयों के कारण शहीद हो रहे हैं ? इसलिए हमें देखना चाहिये कि हम में अपराध कहां है।

वास्तव में हमने विदेश नीति के कुछ पहलुओं में भारी गलती की है। विदेश नीति के तीन अंग होते है। एक सिद्धांत जो परिस्थितियों के साथ साथ बदलने चाहिये दूसरे घात नीति और तीसरे कूटनीति।

हमारी नीति का सिद्धांत संक्षेप में गुटों से अलग रहना है जो एक मंत्र बन चुका है जसे उसके उच्चारण मात्र से हमारी सभी समस्याएं हल हो सकती है। ऐसी धारणा बन गई है कि गुटों से अलग रहने की नीति को हमने जन्म दिया है। वास्तव में इंडोनेशिया, लंका और बर्मा भी गुटों से अलग है किन्तु उन्हें कोई अलग नहीं मानता।

इतिहास पर दृष्टि डालें तो अमरीका भी गुटों से अलग रहा है किन्तु उस नीति का प्रभाव केवल यूरोप के झगड़ों पर पड़ता था। किन्तु हम गुटों से इस प्रकार अलग है कि भले ही उससे हमें लाभ हो या हानि। राजनीति की शब्दावली में जो देश आपस में लड़ रहे हों उन्हें युद्धव्यवसायी देश कहा जाता है गुटों से अलग नहीं।

हम अमरीका और रूस गुटों में ग्रस्त राष्ट्र इसीलिए तो कहते है कि उनमें शीतयुद्ध हो रहा है किन्तु उन्होंने एक दूसरे की भूमि पर तो कब्जा नहीं किया जबकि चीन और पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः हमें गुटों से कैसे कहा जा सकता है? हां इतना कहा जा सकता है कि हमारी किसी से सैनिक संधि नहीं है।

चाहें हम गुटों से अलग रहने की नीति का पालन कर रहे है तो भी चीन के आक्रमण के समय हमने पश्चिम से बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त की है जबकि हमें कहा जाना था कि सैनिक सहायता प्राप्त करने से हम शीतयुद्ध में ग्रस्त हो जाएंगे।

चीनियों के लौटते ही हम भूल गये कि हमें पश्चिम के देशों से सहायता प्राप्त हुई थी। यह बात इससे लक्षित हुई है कि हमने किस भद्दे ढंग से हवाई अभ्यास किया और वाइस आफ अमरीका से समझौते की कैसी स्थिति रही।

भारत सहायता प्राप्त किये बिना चीन का मुकाबला नहीं कर सकता और अब तो पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर मुकाबला करना होगा। उसके लिए हम पश्चिम से बड़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया तो यह भारत के लिए गंभीर चेतावनी थी किन्तु हमने चीन की तिब्बत पर प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया और चीन से मैत्री बढ़ाने का प्रयास करने लगे। भारत चीन मैत्री संघ बने और सरकार के उन्हें संरक्षण प्रदान किया। जब मैंने १९६० में चीन के विस्तारवादी उद्देश्य का उल्लेख किया तो प्रधान मंत्री ने कहा कि १९५० से यह समस्या हमारे सामने है। और प्रधान मंत्री की ओर चीन के नाम एक पत्र में इस बात का उल्लेख था कि चीन की इन कार्यवाहियों से भारत के लोग आवेश में आ जाएंगे। जब चीन की आक्रमणकारी नीति को छिपाया न जा सका तो प्रधान मंत्री ने कहा कि हम साम्यवादी चीन के विरुद्ध नहीं किन्तु विस्तारवादी चीन के विरुद्ध हैं। किन्तु हमारे साम्यवादी मित्र विस्तारवादी साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं।

१९५४ में हमने चीन के साथ संधि की किन्तु सीमाओं के बारे में कोई संधि न की। उनके नक्शों में भारत के क्षेत्र को चीन का क्षेत्र दिखाया गया और हमारे आपत्ति करने पर उन्होंने कह दिया कि वे पुराने नक्शे हैं। तिब्बत में हमने अपने अधिकार तिब्बतियों को नहीं बल्कि चीनियों को सौंप दिये। इंगलैंड भारत के अधिकारों के प्रति सचेत रहा था अतः हर संधि में उन्होंने तिब्बत को भी स्थान दिया था।

आज स्थिति क्या है? हमें अपमान जनक हार का मुंह देखना पड़ा है। कुछ मानवतावादी राष्ट्रों ने कोलम्बो प्रस्ताव रखे जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया और अब डेढ़ साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और चीन उन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नही हम यह बतला रहे है कि वे प्रस्ताव सम्मानजनक हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। चीनी वार्ता को निलम्बित किये जा रहे हैं क्योंकि वे जानते है कि वे हम से अपनी इच्छा अनुसार बातें स्वीकार करवा लेंगे।

श्री मसानी ने बताया है कि श्री लंका के प्रधान मंत्री ने चीन को भारत की ओर से आश्वासन दिया है कि चीन द्वारा छोड़े गये क्षेत्र पर भारत कब्जा नहीं करेगा। यह बात

[श्री कृपालानी]

गलत भी हो पर यह निश्चित है कि भारत उस पर कब्जा नहीं करेगा। अब सरकार कहती है कि इसका निर्णय सेना पर छोड़ दिया गया है किन्तु सच तो यह है कि किसी भी अवसर पर सैनिक अधिकारियों से परामर्श नहीं किया जाता। हमारे राजनीतिज्ञ इस खतरे को नहीं समझते कि हमारी सेनाएं पहाड़ी की तलहटी पर है और चीनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं और हमने अपनी हानि को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया।

हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। पाकिस्तान और चीन इसी नीति का पालन कर रहे हैं; चीन और पाकिस्तान के साथ तो हमारे राजनयिक सम्बन्ध है किन्तु इजराइल हमारे साथ सम्बन्ध बनाने के लिए तैयार है तब भी हम उससे सम्पर्क नहीं बना रहे।

पंजाब के पानी के सम्बन्ध में संधि करते समय हमारा हाथ ऊपर था किन्तु उस समय हमने उस का लाभ उठाकर सभी समस्याओं को हल नहीं किया। गांधी जी अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देते थे किन्तु हम सदा अवसर को हाथ से खोते रहे हैं और प्रतिरक्षा मंत्री यह नहीं जानते कि हमने कुछ प्रगति की है, दो सेवाओं का एक साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता।

बहुत शक्तिशाली देश भी अकेले किसी अन्य देश का मुकाबला नहीं कर सकते, दो राष्ट्रों का एक साथ मुकाबला करनेकी बात तो दूर रही।

पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हत्याकाँड तभी बन्द हो सकता है जब आसाम तथा त्रिपुरा में अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों को वहां से न निकाला जाये और उन्हें भारत में ही रहने दिया जाये। अतः इस विषय पर कोई समझौता होने की आशा नहीं है। हम भारतीय मुसलमानों को भारत छोड़ने के लिये मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार के समक्ष यही एक रास्ता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो भी व्यक्ति भारत आना चाहे, उसे यहां आने की अनुमति दी जाये। लोगों के समय समय पर अपमान तथा वध से यह कहीं अधिक अच्छा है। पाकिस्तान ने चौथी बार यह शरारत की है। पाकिस्तान किसी भी संधि पर अमल नहीं करेगा। हमें पाकिस्तान से कोई समझौता करने की बजाय अल्पसंख्यकों की सहायता करनी चाहिये। और जिन मुसलमानों ने हिन्दुस्तान को अपना घर बना लिया है उन्हें यहीं रहने दिया जाये। हालांकि यह रास्ता अपनाना बड़ा कठिन है परन्तु मातृभूमि के टुकड़े करने से यह कहीं अच्छा है।

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई उत्तर): विश्व में जो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। ये परिवर्तन किसी एक देश तक ही सीमित नहीं हैं अपितु विश्व के दो सब से शक्तिशाली देशों—रूस तथा अमरीका—की विदेश नीतियों में भी इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए काफी फर बदल हुआ है। अमरीका में विदेश नीति का सदैव पुनर्मूल्यांकन किया जाता रहा है।। श्री डलेस के समय में भी यह पुनर्मूल्यांकन हुआ था। और यह निर्णय किया गया था कि अमरीका की नीति साम्यवाद के विस्तार को रोकने की है। परन्तु पिछले कुछ महीनों से उस नीति की छान बीन की जा रही है। जैसा कि अमरीकन समाचार पत्रों से पता चलता है, उस छान बीन के संक्षेप में ये निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह है कि बदलते हुए युग में अमरीकन विदेश नीति के बहुत से मूल तर्क अवैध माने जायेंगे। दूसरा यह है कि विदेश नीति में दूरगामी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और तीसरा यह कि अमरीकी जनता को इन से अवगत

कराना होगा । अमरीका जैसा शक्तिशाली देश अब यह मानने लगा है कि वह विश्व के अन्य राष्ट्रों से मनमानी नहीं करा सकता । इसका अर्थ है कि अब राष्ट्रों के महत्व को मान्यता दी जाने वाली है और यह महसूस किया जाने लगा है कि किसी देश को धन देकर खरीदना असंभव है । यह तटस्थता की नीति का ही परिणाम है ।

सीनेटर फुलब्राइट के वक्तव्य से भी अमरीकी नेताओं पर काफी प्रभाव पड़ा है । जो सीनेटर फुलब्राइट ने कहा है कि अमरीकी विदेश नीति कुछ कल्पनाओं पर आधारित है और जब तक उनका खण्डन नहीं किया जाता, तब तक हम विश्व शांति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। उनका कहना है कि यह समझना कि साम्यवादी गुट ऐसे शासनों का एक गिरोह है जो वास्तव में शासन नहीं है अपितु संगठित षडयंत्र मात्र है , जो स्वतंत्र राष्ट्रों को नष्ट करने पर उतारू हैं। एक कल्पना मात्र है और विश्व शांति के हित में अमरीका को ऐसी बातों को तिलांजलि दे देनी चाहिये । उन्होंने और भी बहुत सी बात कहीं हैं और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं ।

इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जेनेवा में हो रहे १७ राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में पिछले दो वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि तटस्थ राष्ट्र कुछ निष्क्रिय हो गये गये हैं और वे दोनों पक्षों की किसी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन युद्ध में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग है । दक्षिण वियतनाम में शांति स्थापित करने में हमारे देश का काफी योगदान रहा है । वियतनाम में रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से जंगलों को वृक्षों के पत्ते उड़ाकर साफ कर दिया गया है जो कि रासायनिक युद्ध की शुरुआत है । वहां पर काफी संख्या में अमरीकन सैनिक मौजूद हैं। और समय समय पर वहां पर क्रांतियां होती रहती हैं। जहां तक हमारा संबंध है, वियतनाम जर्मनी से भी गम्भीर समस्या बन गया है ।

दो-तीन घटनायें और हुई हैं। एक चीन तथा सोवियत संघ के बीच आपसी संबंधों के बारे में है । । उनके बीच जो मतभेद हैं वे सैद्धांतिक नहीं हैं अपितु वे चीनी विस्तारवाद के कारण उत्पन्न हुए हैं। चंगेज खां के समय से चीन ३ लाख वर्ग मील किलोमीटर क्षेत्र का दावा करता आ रहा है जिस में सोवियत एशिया के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। वह प्रत्येक पड़ौसी देश को हड़पना चाहता है। पिछले तीन हजार वर्षों से उसका यही इतिहास रहा है ।

भारत-चीन सीमा के बारे में स्थिति यह है कि एक ओर तो पाकिस्तान तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच एक समझौता है और दूसरी ओर , भारत का सामना करने का जहां तक सम्बन्ध है, चीन तथा पाकिस्तान में सांठ गांठ हो गई है ।

जेनेवा में आर्थिक सम्मेलन हो रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । पिछले कई वर्षों के लगातार प्रयत्न से यह सम्मेलन हो पाया है और भारत ने इस संबंध में काफी रुचि दिखाई है । लेकिन यह सम्मेलन विश्व में हुए परिवर्तनों का द्योतक है । अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब कि आर्थिक क्षेत्र में 'एक विश्व' के सिद्धांत का अधिकाधिक विस्तार हो रहा है ।

[श्री कृष्णा मेनन]

लैटिन अमरीका में भी परिवर्तन हुए हैं--ब्राजील में क्रांति हुई है जिसके परिणामों का इस समय अनुमान लगाना कठिन है ।

अब मैं तटस्थता की नीति के बारे में कुछ बातें कहूंगा। मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि तटस्थता इस देश की विदेश नीति नहीं है । परन्तु यह परिस्थितियों द्वारा हम पर थोपी गई है । देश की सुरक्षा और भलाई की दृष्टि से तथा विश्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से हमने यह तरीका अपनाया है। इसमें समय समय पर काफी परिवर्तन हुए हैं। देशों के गुटों में बंटे होने के कारण ही तटस्थता की नीति का पालन करना जरूरी हो गया है।

तटस्थता की नीति के कट्टर विरोधी भी अब इसके महत्व को समझने लगे हैं।

अब विश्व में दो ही गुट नहीं रहे हैं, अपितु अनेक गुट उत्पन्न हो गये हैं । कुछ देश ऐसे हैं जो आण्विक हथियारों के खिलाफ हैं। दूसरी ओर, चीन विश्व के विभिन्न भागों में मित्रता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है । अफ्रीका के देशों में भी एक या अन्य गुट में शामिल होने की प्रवृत्ति है, जैसे कुछ फ्रांस की ओर खिंचते हैं तथा अन्य आपस में ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में तटस्थता की नीति की और भी अधिक आवश्यकता है ।

विकसित देश अब यह अनुभव करने लगे हैं कि शक्ति संतुलन और अपने देशवासियों का जीवन स्तर बनाये रखने के लिये अविकसित देशों का विकास करना जरूरी है। अमरीका में भी गरीबी है और सब बातों के होते हुए भी वहां की जनसंख्या के पांचवें हिस्से को अवसर प्राप्त नहीं होते। इस का कारण यह है कि विश्व के सब देश विकसित नहीं हुए हैं और उन में बहुत असामानता है ।जो यह कहते हैं कि सरकार की तटस्थता की नीति असफल रही है, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये कि हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों ने गुटों से दूर रहना पसन्द किया है क्योंकि देश की अन्दरूनी मामलों में स्वतन्त्रता के बल पर ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है । अतः जब तक हम अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं और अपने देश के भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय करना पसन्द करते हैं, तब तक हमें तटस्थता के सिद्धान्त को तिलाजलि नहीं देनी चाहिये क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र की स्वतन्त्रता का द्योतक है। चीन और पाकिस्तान हमारे दो शत्रु हैं अतः ऐसी स्थिति में अपनी तटस्थता की नीति का त्याग कर के दूसरे लोगों के झगड़े में पड़ना और भी खतरनाक होगा। जब तक कि हम इस मामले में पाकिस्तान के पद चिन्हों पर न चलें जो कि पाश्चात्य देशों के गुट में भी शामिल है और अन्यों में भी और अपने स्वार्थ के लिये वे देश इस स्थिति को बर्दाश्त किये हुए हैं । परन्तु हम वैसा रास्ता नहीं अपना सकते ।

हमारी तटस्थता की नीति दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करने में बाधक नहीं रही है। तटस्थता का अर्थ यह है कि अन्य देशों से अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध बनाये रखने, और यहां तक कि सैनिक सामग्री प्राप्त करने में, हम पक्षपात से काम न लें । यही कारण है कि हम विश्व के अनेक देशों से सैनिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जब तक किसी प्रकार की सहायता की प्राप्ति से हमारी अर्थ व्यवस्था पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता है या हमारी प्रगति में बाधा उपस्थित नहीं होती है तब तक ही हमारी तटस्थता कायम है अन्यथा नहीं ।

हम इतिहास में यह नाम पैदा नहीं करना चाहते कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है। जितना अधिक निर्धन तथा विशाल एक देश होता है, उतनी ही अधिक उस की समस्यायें होती हैं। युद्ध में सच बोलने पर भी रोक लग जाती है। अतः इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शांति बनाये रखना अनिवार्य है। विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन को दृष्टि में रखते हुए तटस्थता की नीति का ईमानदारी से पालन करना हमारे लिये बहुत जरूरी हो गया है और मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि यह सैनिक संधियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये अपितु आर्थिक तथा अन्य मामलों में भी देश की स्वतन्त्रता बनाये रखने की नीति का पालन किया जाना चाहिये।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हम उस से तभी बातचीत कर सकते हैं जब भारतीय राज्य क्षेत्र हमें वापिस लौटा दिया जाय। हम ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है और प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि हम केवल उन के आधार पर ही चीन से बातचीत कर सकते हैं। हमें इस फैसले में और कोई फेरबदल नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस से हमारी स्थिति कमजोर पड़ जायेगी। कोलम्बो ग्रुप की सदस्यता को सीमित रखना भारत के लिये खतरनाक सिद्ध होगा क्योंकि चीन बारी बारी उन पर प्रभाव डाल सकेगा। और हो सकता है कि उस के प्रभाव में आ कर वे देश कोलम्बो प्रस्तावों को वापिस लें लें। अतः कोई न कोई युक्ति निकाली जानी चाहिये जिस से कोलम्दो ग्रुप के देशों की सदस्यता में वृद्धि की जा सके ताकि वे हम से मनमानी न करवा सकें।

सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि हमारे विदेश प्रचार के ठीक न होने के कारण ही हम अधिक संख्या में अफ्रीकी देशों को अपना मित्र बनाने में सफल नहीं हुए हैं। मैं इस मामले में सरकार की वकालत नहीं कर रहा हुं, परन्तु अपने थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि दूतावासों तथा लोक सम्पर्क अधिकारियों को भेजी गई प्रचार सामग्री से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। देश की नीति से ही अन्य देशों के लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। हम अपनी सचाई तथा साहस से ही अन्य देशों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभी हाल में स्वतन्त्र हुए देशों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विभाजन रेखा को अन्तिम रेखा स्वीकार नहीं करता अतः अपनी सीमा के विस्तार की दिशा में अभी उस ने शुरूआत ही की है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि शक्तिशली पड़ौसी देश हमारे सब से बड़े शत्रु हैं। हमें पाकिस्तान की ओर के खतरे से सावधान रहना चाहिये और उस के विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का सामना करना चाहिये। यदि हम पाकिस्तान के खतरे का सामना नहीं कर सकेंगे तो इस से हमारे देश के लोगों के नैतिक बल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस के अतिरिक्त, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पाकिस्तान तथा चीन दो पृथक पृथक शत्रु नहीं हैं अपितु वे दोनों एक शत्रु हैं। जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, पाकिस्तान की स्थिति में १९५५ से काफी परिवर्तन हो गया है। पश्चिमी देशों से संधि करने और उन से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात् पाकिस्तान भारत से मनमानी कराने पर उतारू है। उस समय हमारे प्रधान मंत्री को पश्चिमी देशों ने यह उत्तर दिया था कि हम भारत को भी हथियार देने के लिये तैयार हैं। अतः हमें इस बदली हुई परिस्थिति का सामना करने के लिये जागरूक रहना चाहिये। सीटो पैक्ट चीनी साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिये किया गया था। पाकिस्तान को यह सैनिक सहायता उसी दृष्टि से दी गई थी। अतः यह एक विचित्र बात है कि इस के बावजूद भी, पाकिस्तान द्वारा चीनसे सम्बन्ध स्थापित किये जाने पर पश्चिमी देशों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। रूस चीन को पैट्रोल तथा अन्य वस्तुयें बहुत अधिक मात्रामें देता था परन्तु भारत पर चीनी आक्रमण के पश्चात् रूस ने यह सब कुछ देना बन्द कर दिया। अतः हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिस से हमारी

[श्री कृष्ण मेनन]

सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाये। पूर्वी बंगाल, आसाम से मिला हुआ है अतः पाकिस्तान अवश्य ही ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या में फेरबदल करने की कोशिश करेगा, ताकि वह बाद में जनमत संग्रह के आवाज बुलन्द कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अब भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री कृष्ण मेनन : देश की रक्षा के सम्बन्ध में हमें जो साज सामान मिला है और काश्मीर के सम्बन्ध में राष्ट्रों की नीतियों के लिये हम इंगलैंड और अमरीका के प्रतिनिधियों के आभारी रहे हैं ।

यह विचित्र बात है कि पाकिस्तान से सम्बन्धित वादविवाद तो गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है किन्तु कश्मीर देश का अभिन्न अंग होते हुए भी उस की चर्चा विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। काश्मीर का विभाजन भारत का विभाजन है। काश्मीर पर आक्रमण भारत पर आक्रमण है। यह बात आज नहीं बल्कि १९४८ में ही कह दी गई थी, । कुछ लोग कहते हैं कि इस बात का विचार बाद में आया था किन्तु यह तो १९४८ में ही कह दिया गया था।

गोपालस्वामी अय्यंगार ने कहा था कि हम दूसरे पक्ष के इस दावे का खण्डन करते हैं कि काश्मीर का भारत में विलय अस्थायी है २६ अक्तूबर, १९४८ को काश्मीर का जो विलय हुआ था वह वैध था और भारत ने जम्मू और काश्मीर को विध्वंस और आक्राताओं से बचाने के लिए उस का विलय किया था ।

शेख अब्दुल्ला को रिहा करने का मामला आन्तरिक है। इस का सम्बद्ध मानव अधिकारों से है और जम्मू और काश्मीर सरकार ने भले ही केन्द्र के परामर्श से अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन किया है। अतः सरकार ने पुनः यह कह दिया है कि काश्मीर का विलय अपरिवर्तनीय है।

बहुत समय पहले टैक्सास के बारे में प्रश्न पैदा हुआ था कि वह अमरीका से अलग हो सकता है अथवा नहीं, और वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जब एक बार टैक्सास संघ में प्रविष्ट हो गया तो वह अलग नहीं हो सकता।

हम ने जनमत संग्रह का कभी आश्वासन नहीं दिया और यदि दिया भी था तो अब अन्य अनेक बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। विश्व भर में जनमत संग्रह से ऐसा निर्णय केवल एक ही बार हुआ है। तर्क के लिए भले यह बहुत अच्छा हो किन्तु एक दिन में उन लोगों द्वारा राजनीतिज्ञ नहीं हैं किसी पत्र पर चिह्न लगवाने मात्र से ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता।

पुनः काश्मीर पर सुरक्षा परिषद् में चर्चा होने वाली है। हमें बार बार इस विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद् में छै राष्ट्र सदस्य हैं जिन के लिए "आत्म-निर्णय" शब्द का चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है। अतः यह आवश्यक है कि वहां पुरानी बातों का उल्लेख करना चाहिये और बताना चाहिये कि १५ अगस्त को काश्मीर पर आक्रमण किया गया था ।

अब हमारे ही एक साथी यह आशंका प्रकट कर रहे हैं कि काश्मीर में संविधान सभा का आह्वान करने से ही यह स्थिति पैदा हो जाती है कि काश्मीर के लोगों को आत्म-निर्णय का अधिकार देना चाहिय किन्तु काश्मीर की संविधान सभा को राज्य के अध्यक्ष ने बुलाया था और सभा ने प्रस्तावना में ही कहा था कि विलय के आधार पर संविधान सभा अपना कार्य आरम्भ करती है। जब सुरक्षा परिषद्

ने कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान सभा शीघ्रता से विलय को स्वीकृत कर ले तो हम ने कहा था कि संविधान सभा विलय का परिणाम है और वह इस के विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार नहीं रखती ।

हमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह यह अनुभव करना चाहिये कि हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध हमारे ही क्षेत्र से नहीं हो सकता । संवाददाताओं का कहना है कि राज्य विभाग युद्ध विराम रेखा को ५०० गज से बढ़ा कर ३ मील लम्बा करना चाहती है और उस पर संयुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाना चाहती है । हम सदा इस का विरोध करते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने का यह अभिप्राय है कि संयुक्त राष्ट्रीय आपातकालीन सेना बुलाई जा रही है और हम उन्हें अपनी भूमि में या युद्ध विराम की रेखा से पर भी नहीं चाहते क्योंकि वह भी हमारा प्रदेश है ।

दक्षिण पूर्व एशिया में सैनिक संधियां स्थापित करने का सुझाव भी आपत्तिजनक है ।

कहा जाता है कि एक अमरीकी राजनीतिज्ञ ने स्वतन्त्र काश्मीर का सुझाव दिया है । वास्तव में संविधान सभा में इस पर भी चर्चा हुई थी और शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि ऐसा निर्बल राज्य जिस की सीमायें दुर्गम हों जो अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा न कर सकता हो स्वतन्त्र नहीं रह सकता जब तक आस पास के देश उस की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने का आश्वासन न दें । सिवाय अमरीकी कश्मीर के कोई स्वतन्त्र काश्मीर नहीं हो सकता जब कि एक ओर शक्तिशाली रूस और चीन के राष्ट्र हैं और दूसरी ओर शत्रुभाव रखने वाला पाकिस्तान है ।

विदेश नीति का आधार आत्म हित होता है । हमें यह कहना है कि हम ने आयोग को आने की अनुमति दी उचित नहीं क्योंकि यह देश अतिथि सत्कार में विश्वास रखता है । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उस के संकल्प को भी स्वीकार किया जाए ?

अतः हमें सुरक्षा परिषद् को बताना है कि काश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह भारत में हो रहा है । पाकिस्तान ने वहां आक्रमण किया था और अब वे युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन कर रहा है ।

यह कहना आवश्यक नहीं कि अब इतनी देर हो गई है कि आत्म निर्णय नहीं हो सकता बल्कि यह प्रश्न तो देश से अलग होने का है और हम इस आधार पर खून खराबा नहीं चाहते कि काश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्या है ।

अन्य देशों में क्या हो रहा है । क्या अफ्रीका में उपनिवेशों से मुक्त होने वाले देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया है जब कि साम्राज्यवादी शक्तियां अब भी वहां घुसने का प्रयत्न कर रही हैं क्यों वे कभी भी अपनी आदतें नहीं बदलते । हमारी नीति यही रही है कि हम सब ओर से सहायता प्राप्त कर के गुटों से अलग रहने की नीति को सुदृढ़ बनाएं ।

श्री उयानाथ (पट्टकोट्टई) : आज के हिन्दुस्तान टाईम्स के अनुसार अमरीका का सातवां बेड़ा हिन्द सागर में घुस आया है । हम पहले ही पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव का मुकाबला कर रहे हैं । प्रधान मंत्री को अब यह घोषणा कर देनी चाहिये कि वे अमरीकी बेड़े के हिन्द सागर में प्रवेश का अनुमोदन नहीं करते ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

[श्री उमानाथ]

पांडीचेरी को "ग" राज्य का स्तर दिया गया है ताकि वहां लोकतंत्र का विकास हो अतः हमें देखना है कि उसे दिया गया धन फजूल खर्च तो नहीं किया जाता ।

उस राज्य में मध्यवर्ग के मकान बनाने के लिए बड़ी बड़ी राशियां दी जा रही हैं। हाल ही में वहां के एक विभाग ने एक महिला को इस योजना के अन्तर्गत २५००० रुपया दे दिया है जब कि उसे पता था कि वह महिला बहुत धनी है । इतना रुपया उसे इसलिए दिया गया कि वह वहां के वर्तमान सहकार मंत्री की पत्नी है ।

डेढ़ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को १५००० रुपया ट्रेक्टर खरीदने के लिए दिया गया था । वह धन खर्च हो चुका है और ट्रेक्टर अभी तक नहीं खरीदा गया । वह व्यक्ति सामुदायिक विकास और कृषि मंत्री के भाई है ।

राज्य सरकार ने एक व्यक्ति को वार्निश तैयार करने के लिए अलकोहल का लाइसेंस दिया गया था । उसने ४००० गेलन अलकोहल महाराष्ट्र राज्य को भेज दिया हालांकि महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी किया गया कोई आयात लाइसेंस नहीं दिखाया । नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक था । वह व्यक्ति राजस्व मंत्री का पुत्र था ।

उस राज्य में परिवार पोषण का बोल बाला है । अभी तीन मास एक व्यक्ति अपर डिवीजन कर्ल्क नियुक्त किया गया किन्तु अब वह मंत्रिमंडल में अधीक्षक है और शीघ्र ही अवर सचिव बन जायगा । उसकी योग्यता यही थी कि वह मुख्य मंत्री का पुत्र था । हम ने राज्य को जो धन लोगों को व्यय के लिए दिया है उसे इस प्रकार लुटाया जा रहा है।

भ्रष्टाचार का एक और तरीका यह है कि मंत्री नगरपालिका परिषदों और सहकारी समितियों तथा न्यासों के निदेशक बन जाते हैं और उन का पैसा खाते है।

हाल ही में पांडीचेरी नगरपालिका प्रशासन ने मोटरों के अड्डे का किराया वसूल करने का काम कम बोली वाले व्यक्ति को दे दिया था । अधिकतम बोली वाले द्वारा दावा करने पर मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि याचिकाकार को उस अवसर पर हटा न दिया जाता तो बोली बहुत ऊंची जाती । इस निर्णय पर नगरपालिका के महापौर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि महापौर स्वयं मुख्य मंत्री हैं। सरकार को इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप कार्यवाही करके करनी चाहिये।

५ मार्च के मातभूमि में लिखा है कि पांडीचेरी के मुख्य मंत्री ने माही में कहा कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि हमारे प्रदेश में भारतीय निधियों को लागू किया जाए । क्या सब प्रयत्न पांडीचेरी को भारत के संविधान से बाहर रखने के लिए नहीं हैं।

वहां के मुख्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की बन्द बैठक में भारत के राष्ट्रपति का नाम लेकर गालियां निकाली और शिष्टाचार की सभी सीमाओं को पार कर दिया। यह सब देशद्रोह है और आशा है कि आप माननीय मंत्री से इन सब बातों का उत्तर देने के लिए कहेंग ।

वैदेशिक कार्य राज्य मंत्री ने बताया है कि पांडीचेरी की सरकार ने अन्य राज्यों के वकीलों द्वारा पांडीचेरी के न्यायालयों में मुकदमा लड़ने का इस आधार का विरोध किया है कि अन्य राज्यों के वकील भारतीय विधियों का प्रशासन कर सकते हैं। भला भारतीय वकील पांडीचेरी के नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे नहीं कर सकते ?

वहां के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए ही मैं आग्रह कर रहा हूं कि वहां अधिवक्ता अधिनियम लागू किया जाए । मुख्य मंत्री इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि वकील उपलब्ध न होने पर नागरिकों के प्रति न्याय नहीं होगा जिस से उन में भारतीय विधियों के प्रति रोष फैलेगा । इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार का कर्तव्य है कि वह पांडीचेरी के नागरिकों की रक्षा के लिए वहां अधिवक्ता अधिनियम को लागू करें।

पांडीचेरी में बहुत समय से वह फ्रांसीसी विधि लागू है जिस के अन्तर्गत बिना अनुमति के कोई सभा नहीं की जा सकती और न कोई जलूस निकाला जा सकता है । उस राज्य को "ग" राज्य का स्थान देने के तुरन्त बाद में इस कानून के अन्तर्गत शहीद दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह दिवस ३० जुलाई १९६३ को उन शहीदों की याद में मनाया जा रहा था जिन्होंने पांडीचेरी की आज़ादी के लिये लड़ते हुए फ्रांसीसियों की गोलियों से जानें दी थीं ।

हमारे संविधान के अधीन जो संसदीय संस्थाएं वहां स्थापित की गई है वह खतरे में हैं। जब विधान सभा में 'अविश्वास प्रस्ताव' लाया जाने वाला था तो मुख्य मंत्री ने गुंडों की सहायता से विरोधी दल के नेता और उनकी पत्नी को पिटवा दिया । तभी से विरोधी दल ने सभा में उपस्थित होना बन्द कर दिया । १९५१ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश सचिव श्री गूबर्ट ऐसे गुट के नेता है जो पैसे और शराब की सहायता से पांडीचेरी में सब कुछ कर सकते हैं। वही श्री गूबर्ट आज कल वहां के मुख्य मंत्री हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि सरकार वहां हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वहां के लोगों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): मुझे प्रतिरक्षा मंत्री के शब्दों पर विश्वास नहीं आता । क्योंकि इन्होंने लद्दाख और नेफा को हाथ से जाने दिया । शुक्र है कि अब उन्हें समझ आई है ।

हम शुरू से चिल्ला रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला को न छोड़ा जाय । किन्तु यह तो अंधों की नीति है जो उसे छोड़ दिया गया है । हम जानते थे कि वह यही कुछ कहेगा जो वह आज कह रहा है । वह आज यह कहने का साहस करता है कि डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के बारे में जांच की जाए और कि उसे उनकी मृत्यु हो जाने तक पता नहीं था कि वे बीमार हैं। सच यह है कि मैं ने स्वयं कई बार उन्हें टेलीफोन पर बताया था किन्तु मुझे डाक्टर साहब के पास जाने और उन का उपचार करवाने की अनुमति नहीं दी गई थी । काश्मीर को अकारण ही अन्तर्राष्ट्रीय मामला बना रखा है । शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बजाय यह मामला सुरक्षा परिषद् से ले लेना चाहिये था ।

अब विदेश नीति को लीजिए । मैं कहता हूं भारत की कोई भी विदेश नीति है ही नहीं । यदि हमारी गुटों से अलग रहने की नीति है तो हम ने हंगरी पर किये गये आक्रमण का क्यों विरोध नहीं किया, इजराइल के साथ अब तक कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किए? चीन जब तिब्बत में नर संहार कर रहा था तो हम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया ? यह तो केवल भय की नीति है ।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

मलेशिया के प्रधान मंत्री ने साहसपूर्वक कहा कि वह पाकिस्तान के कामों का विरोध करता है, किन्तु अब क्यों हम ने इंडोनेशिया का विरोध नहीं किया । यदि हम गुटों से अलग हैं तो हमें सत्य कहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें सब जगह अपमानपूर्वक निकाला जा रहा है । जैसे श्रीलंका, बर्मा, जंजीबार, कीनिया, और दक्षिण अफ़्रीका । आज हमें कोई भी राष्ट्र पसन्द नहीं करता तो हम किन देशों से अपनी अच्छाई का प्रमाणपत्र पाना चाहते हैं । हमारे अपने लोग राष्ट्र को ऐसा प्रमाणपत्र देने के लिए तैयार नहीं हैं। रूस को हम परम मित्र समझते थे किन्तु वही चीन को शस्त्रास्त्र और पेट्रोल देता रहा है । वास्तव में निर्बल का कोई मित्र नहीं होता । १९६२–६३ में हांगकांग को संभरण किये गये पेट्रोल की मात्रा को पढ़ कर आश्चर्य होता है। वास्तव में वह सारा पेट्रोल भी चीन को ही जाता रहा है किन्तु हम ने इंगलैंड से नहीं कहा कि वह ऐसा न करे।

श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि केवल प्रचार से कुछ नहीं होता । किन्तु मुझे विश्वास है कि हम प्रचार के अभाव के कारण ही विफल हुए हैं। फिर ईश्वर बचाये हमारे प्रचार कर्ताओं से । ऐसे लोगों को प्रचारार्थ बाहर भेजा जाता है जिन्हें भारत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता । मुझे इस विदेश नीति में कहीं कोई सफलता लक्षित नहीं होती ।

विदेश नीति से हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ है । पांडीचेरी की बात करते हुए मेरे माननीय मित्र सातवें बेड़े की बात करने लगे । सातवें बेड़े के अभ्यास करने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं । कठिनाई तब होती है जब अपने विचार बेचे जायं । सातवे बेड़े से अधिक खतरा देश में उन लोगों से है जो बाहर शक्तियों के ऐजन्ट हैं और देश को गुमराह करते हैं । आज इस देश में खुले आम पाकिस्तान के पक्ष में भाषण होते हैं । परन्तु उन्हें रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

इसी प्रकार गोआ, दमन, दीव, पांडीचरी, माही इत्यादि राज्य क्षेत्रों को अलग रखने का कोई मतलब ही नहीं । उन्हें हर हालत में भारत में मिला लिया जाना चाहिये । यदि चन्द्रनगर को भारत के साथ मिलाया जा सकता है तो दूसरों को भी मिलाया जा सकता है । उपरोक्त क्षेत्रों को भी तमिलनाड अथवा महाराष्ट्र में मिलाया जा सकता है । इन क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृति की बात करना बिल्कुल बेकार है । हमारी नीति प्रायः अर्थ हीन ही रही है और इसे कायरों की नीति ही कहा । मेरा निवेदन यह है कि यदि हमारी नीति तनिक भी सफल हुई होती तो संसार भर में जो हमारी बदनामी हुई है, उससे हम बच जाते ।

हजारों हिन्दुओं की हत्या हो रही है और हम इन्हें हिन्दू कहने से भी घबरा रहे हैं । हम शेख अबदुल्ला को सब तरह की आजादी दे रहे हैं । समझ में नहीं आता कि किस मतलब के लिए पाकितान के गृह कार्य मंत्री को बातचीत के लिए बुलाया गया। उसने आते ही कहा कि उन २८ लाख मुसलमानों को मत निकालो जो भारत में घुस चुके हैं । हम कुछ नहीं कर पा रहे । बताइये यह किस तरह की हमारी विदेश नीति है । मेरा निवेदन है कि हमारे उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये जिनके साथ हमारा लोकतंत्रात्मक विचारों के कारण कोई मतभेद नहीं है । लेकिन हम तो बड़े अजीब ढंग से चल रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता कि हमारी तरह के ऐसे कौन से लोक तंत्रात्मक देश हैं जिनसे हम एक मत हो सकते हैं । हम अपने देश को बड़े भारी गढ़े में गिरा रहे हैं जिसमें से निकलना कठिन होगा । हम यह सोच ही नहीं रहे कि हम कहा जा रहे हैं ।

अन्य देशों के हवाई जहाज हमारे क्षेत्रों के ऊपर से उड़ जाते हैं। चाऊ-एन०-लाई भी हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं, परन्तु पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान से माल लाने ले जाने की अनुमति नहीं देता। हमें अपने हितों और आत्म रक्षा का विचार कब आयेगा। मेरा निवेदन यह है कि यह बड़ा जरूरी है कि हमारी नीति का एक विशेष प्रकार का गठबन्धन हो और वह गठबन्धन बुद्धिमान राजनीतिज्ञों और बीर पुरुषों की तरह का होना चाहिये। लाचारी की दशा वाली नीति का निर्माण नहीं होना चाहिये। क्या यह खेदजनक स्थिति नहीं कि सुरक्षा परिषद् में भी हमारी आवाज का कोई प्रभाव नहीं। वहां समुचित ढंग से काश्मीर का मामला नहीं रखा गया।

मेरा आग्रह यह है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सभी दलों को अपने विश्वास में लेना चाहिये। अब समय आ गया है कि विदेश नीति के निर्माण में सब का परामर्श लिया जाय। अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये। श्री कृष्ण मेनन ने जो यह कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे शत्रु हैं और हमें उन का हर फ्रंट पर डट कर मुकाबला करना चाहिये।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने गत १७ वर्षों में देश को आगे ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी इन पर ही रहा है। बिना विभाग के मंत्री भी दल के कार्यशील व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रशासन में काफी शक्ति का निर्माण किया है।

यह ठीक है कि हमें ब्रिटेन और अमरीका से सहायता लेनी चाहिये, परन्तु उनके कहने से पाकिस्तान को काश्मीर भेंट नहीं करना चाहिये। सहायता के कारण उन्हें हमारी नीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अन्य देशों ने भी हमारी भारी मात्रा में आर्थिक सहायता की है। चैकोस्लावेकिया तथा रूस ने हमारी सहायता की है। हमें उनका आभार मानना ही चाहिये।

पाकिस्तान के बारे में यह बात समझ ली जानी चाहिये कि उसकी स्थापना भारत के प्रति घृणा के आधार पर की गई है। जो लोग यह समझते हैं कि काश्मीर का प्रश्न हल कर लिये जाने के बाद भारत और पाकिस्तान की सारी समस्यायें हल हो जायेंगी, वह भ्रांति में हैं। पाकिस्तान की चालों को नंगा करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये। हमें एक बात अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये कि स्वतन्त्रता के १७ वर्ष बाद भी पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं बन पाया है। आज पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भारत के प्रति घृणा के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान्य बात नहीं है। मेरे विचार में जैसे ही पाकिस्तान के साथ भारत की दोस्ती हो जायेगी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव की स्थिति का निर्माण हो जायेगा। आज वहां लोग सैनिक तानाशाही से करा रहे हैं। वहां किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है।

अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार वहां हो रहा है। पाकिस्तान ने न केवल हिन्दु अल्पसंख्यकों के साथ लज्जा जनक व्यवहार किया है प्रत्युत सीमावर्ती प्रान्त के पठानों और बलोचिस्तान के लोगों पर भी अत्याचार किये हैं। हमने शायद उन लोगों के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया जो कि पख्तूनीस्तान के लिए लड़ रहे हैं। हमने ढाका के उन लोगों को भी

[श्री अन्सार हरवानी]

कोई सहायता नहीं दी जो कि सिर उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि कोई न कोई साधन अवश्य निर्माण किया जाना चाहिये ताकि पाकिस्तान में विरोधी आन्दोलन तथा आजादी के लिये लड़ने वालों को सहायता की जाय। जिन देशों में लोग आजादी के लिए लड़ते रहे हैं उनकी हम सहायता करते रहे हैं। पाकिस्तान में आजादी के लिए लड़ने वालों की सहायता हम क्यों नहीं करते।

विदेशों में हमारे विरुद्ध गलत प्रचार हो रहा है। हमें अंग्रेजों का दुम छल्ला रह कर बदनाम किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमें विदेशों में अपना प्रचार कार्य तीव्र करना चाहिये। और केवल उन लोगों को ही राजदूतों के पद पर नियुक्त करना चाहिये जो कि देशभक्त हों और जिन पर भारत की स्वतन्त्रता के आन्दोलन का प्रभाव हो। इस तरह से ही हमारा प्रचार प्रभावशाली हो सकता है। इन शब्दों से मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मनोहरन (मद्रास दक्षिण) : आज हम संकट का सामना कर रहे हैं, और हमारी विदेशनीति के परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रहे हैं। राजनीतिक जीवन में अव्यवस्था और गड़बड़ फैल रही है। विदेशों में हमारे मित्रों की निरन्तर कमी हो रही है। ऐशिया और अफ्रीका के देश जो कि भारत की ओर स्फूर्ति और पथ-प्रदर्शन की ओर देखा करते थे आज हमसे बेमुख हो रहे हैं। सभी हमें सन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं। हमारी एकता और ईमानदारी पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। हमारी कूटनीति डावांडोल है और सुरक्षा खतरे में पड़ी है। सहायता देना भी भारी गलती है इसके अतिरिक्त इस विचार से कि उत्तर कोरिया तथा उत्तर वियतनाम सीमा से परे हमारे घोषित शत्रुओं के बहुत निकट है। उनके दूतावासों को यहां काम करने देना, भारत सरकार की भारी भूल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इन देशों ने चीन का समर्थन किया है और बड़े स्पष्ट रूप में हमारे विरुद्ध रवैय्या अपनाया। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिये। सरकार को विध्वंसक कार्यवाहियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिये। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि साम्यवादी देशों से जो व्यापार तथा सांस्कृतिक शिष्टमंडल मेरा विचार यह है कि भारत सरकार की विदेश नीति में विलम्बपूर्ण तरीके हैं सुस्ती है, तथा दकियानूसी दृष्टिकोण है और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत का अब तक का अन्तर्राष्ट्रीय यश धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर रहा है। प्रधान मंत्री नेहरू का नाम जो पहिले स्फूर्ति दिय करता था अब नहीं करता। चीन के हमलों के बाद जो नीति हमने अपनाई वह हमारे सामने है। चीन प्रजातंत्र का कट्टर शत्रु है। हमें इस देश से अपने कूटनीतिक सम्बन्धों को तुरन्त तोड़ लेना चाहिये। मेरे विचार में हमारे साथ युद्ध करने वाले चीनियों को, भारत में अपने प्रतिनिधि रखने को इस देश में आते हैं उनके प्रति भी हमें काफी सचेत रहना चाहिये। आखिर आपने भारत की रक्षा करनी है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त मैं लंका के भारतीयों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। काफी समय यह मामला लटकता आया है। भारतीय लोगों का जीवन और सम्पत्ति वहां खतरे में है। दक्षिण और पश्चिम श्री लंका में १० लाख से अधिक लोग भारतीय हैं। यह लोग अधिकतर श्रमिक हैं और चाय तथा रबड़ के बागान में काम करते हैं। उनकी भाषा तमिल है। श्रीलंका के समृद्धिशील बागान के विकास में इन श्रमिकों का बड़ा काफी हिस्सा है। इन लोगों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि श्रीलंका एक सुन्दर प्रायद्वीप है। श्रीलंका कि

कल्याण के लिए सैकड़ों तमिल परिवारों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। परन्तु जब उनके कष्टों की बात की जाती है तो हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम उनके घरेलू मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। और फिर वह देश हमारा मित्र देश है। अतः समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण कर रही है। यहां रहने वाले भारतीयों को सब प्रकार के अपमान सहन करने पड़ रहे हैं। सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए तत्काल ध्यान देना चाहिये। भारत सरकार का व्यवहार इस मामले में बहुत उत्साहहीन है। क्या वहां के भारतीय इसी तरह अपमान का जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इसी तरह बर्मा में भी राष्ट्रीयकरण की योजना लेकर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। क्या हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : एक औचित्य का प्रश्न है। मैं आपके विनिर्णय को स्वीकार करता हूं कि समय का अभाव है परन्तु श्री लंका के भारतीयों के विषय में एक कटौती प्रस्ताव है, यदि आप बोलने का अवसर ही न देंगे तो प्रधान मंत्री उत्तर क्या देंगे।

श्री त्यागी (देहरादून) : एक औचित्य का प्रश्न है। कटौती प्रस्ताव तो बिना भाषणों के ही प्रस्तुत माने जायेंगे। यदि सदस्यों द्वारा भाषण न भी दिये जायें तब भी मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वह कटौती प्रस्तावों के उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं।

श्री कु० शिव प्रकासन (पांडिचेरी) : श्री ही० ना० मुकर्जी ने पांडिचेरी की चर्चा करते हुए वहां की नगरपालिका द्वारा की गयी नीलामी और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में कहा। उन्होंने वहां पर राजनीतिक विरोधी पक्ष के विरुद्ध गुंडागर्दी की बात भी कही। मैं इन दोनों बातों का खंडन करना चाहता हूं। पांडिचेरी में अलग न्यायिक व्यवस्था की मांग बहुत पुरानी है जिस का सम्बंध नगरपालिका की नीलामी और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से नहीं है। स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिये गये हैं और हमारे मुख्य मंत्री ठीक ही कहते हैं कि पांडिचेरी के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए।

जिस मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में इतनी बातें कहीं गयी वह वास्तव में क्या हैं। उसमें कहा गया है :—

> "राजनीतिक शत्रुता एवं भेदभाव के आरोपों का कोई आधार है इस बारे में हम सन्तुष्ट नहीं हुए।"

निर्णय में यह और कहा गया है कि :—

> "हमें इस बारे में सन्देह नहीं है कि मेयर ने अपने कर्त्तव्यों का पालन सद्भाव से किया है।" इससे स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्णयों को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया।

जहां तक वहां पर राजनीतिक गुंडागर्दी का सम्बंध है वह गुंडागर्दी साम्यवादियों के पीपुल्स ट द्वारा किये गये। साम्यवादियों द्वारा यह गुंडागर्दी इसलिए की गयी चूंकि निर्वाचनों में उन्हें हार खानी पड़ी और उन को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने में भी असफलता हुई। इसलिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना अनुचित है।

[श्री कु० शिव प्रकाशन]

इसके अतिरिक्त मुझे यह और कहना है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां पर पुलिस है, न्यायालय है और जनता की आम राय भी है। बेहतर यही है कि इन साधनों द्वारा सच्चाई मालूम की जाय ।

इसके पश्चात् मैं पांडिचेरी की तीन मुख्य समस्याओं की ओर निर्देश करूंगा । सब से पहली समस्या उन केन्द्रीय अधिकारियों की है जिन्हें पांडिचेरी में प्रतिनियुक्त किया गया है । आज इतने वर्ष हो गये हैं उनको वहां पर गये हुए इसके बावजूद भी उन्हें वापस नहीं बुलाया गया और वह पदाधिकारी वहीं पर स्थानी प्रशासन का एक अंग बन जाने के लिए कोशिश कर में हैं । वह वहां से लौटना नहीं चाहते । हमारे क्षेत्र में शिक्षित युवक काफी संख्या में हैं और उनके रोजगार की भी समस्या है । यदि वहां से केन्द्रीय पदाधिकारी वापस आ जायें तो अन्य लोगों को अवसर मिल सकते हैं । हमें भी यह अधिकार है कि हम अन्य राज्यों की तरह अपना अस्तित्व बनाये रखें । यदि उन पदाधिकारियों को वहां से वापस बुला लिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जा रहे व्यय में भी कमी हो जायेगी ।

मेरी दूसरी मांग यह है कि पांडिचेरी के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ते दिये जायें । जब अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन तथा भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही दिये जाते हैं तो केवल पांडिचेरी के साथ ही क्यों भेदभाव का व्यवहार किया जाता है । जो वेतन तथा भत्ते अब दिये जाते हैं वह फ्रांसी वेतन क्रमों से भी कम हैं । वहां के कर्मचारियों में इस कारण बहुत असंतोष पाया जाता है । अतः इस अनियमितता एवं भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए ।

एक समस्या वहां के कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने की भी है । वहां कर्मचारी ९, ९ वर्ष से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं । अतः इस अनियमितता को भी दूर किया जाना चाहिए।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं अपनी विदेश नीति के तीन मुख्य अंगों की चर्चा करूंगा । इसकी विचारधारा, उसका कार्यन्वयन तथा उसका प्रचार । हमारी जो विदेश नीति है उसके कारण काफी बाधायें आई, काफी कठिनाईयां आई, परन्तु इसके बावजूद भी वह उचित साबित हुई है। अपनी गुटों से अलग रहने की नीति के कारण ही हम मुसीबत के समय सभी से सहायता प्राप्त कर सके हैं । हमारा देश और इस देश के वासी बहुत महान हैं अतः हमें अपने विश्वास को खो नहीं देना है । भविष्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए । हमारे नेता महान हैं उन और के उद्देश्य भी महान हैं । शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है । गुटों से अलग रहते हुए भी हम ने हंगरी की घटनाओं की आलोचना की । हमारे प्रधान मंत्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गये थे तो क्यूबा के कैस्ट्रो से मिल कर आये थे । इन सब बातों से यही प्रतीत होता है कि जब अन्याय नहीं किया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज बुलन्द करते हैं । अतः तटस्थता की नीति का ठीक अर्थ लगाया जाना चाहिए ।

अब मैं इस नीति के कार्यान्वयन की चर्चा करूंगा । श्री स्वैल का यह कहना गलत है कि हम युद्ध विराम रेखा को पार कर सकते हैं चूंकि उससे युद्ध छिड़ जायगा .... (**अंतर्वाधायें**) । चीन के प्रति भी हमारी नीति स्पष्ट है । हम अपने राज्य-क्षेत्र की रक्षा करेंगे और यदि चीन ने फिर आक्रमण किया तो उसका मुकाबला किया जायगा ।

शेख अब्दुल्ला यदि पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं तो मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि वह कोई समझोता कर सकते हैं तो बेहतर है । परन्तु काश्मीर भारत का एक अंग है

और हमारी सेना वहां की सीमाओं पर तैनात है। हम किसी को अपने राज्य क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे ।

मैं समझता हूं कि श्री लंका, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, तुर्की, मलाया आदि देशों की अवहेलना की है। यही कारण है कि श्रीमती भंडारनायके ने श्रीलंका की संसद में कहा है कि भारत की विदेश नीति श्रीलंका की विदेश नीति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पदाधिकारी ठीक प्रकार से काम नहीं करते जिसके कारण हमारे मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। कम्बोडिया भी हम से पहले की तरह प्रभावित नहीं है। मलाया एक ऐसा देश है जिसमें चीनी आक्रमण के समय हमारे लिए आवाज उठाई थी परन्तु अब हमने उसे बांडुंग सम्मेलन में सम्मिलित किये जाने के बारे में मांग ही नहीं की। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मित्रों का साथ दें तभी वह संकट के समय हमारा साथ देंगे। जब ईराक के राष्ट्रपति आरेफ यहां आये थे तो उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर ले जा कर दिखाना चाहिए था कि किस प्रकार वहां से अल्पसंख्यकों का प्रव्रजन हो रहा है। हम ने देखा था कि तुर्की राष्ट्रपति हमारे प्रधान मंत्री का बहुत सम्मान करते हैं परन्तु काश्मीर के सम्बंध में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल वहां गया तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो प्रतिनिधि वहां पर हैं वह क्या कर रहे हैं? उन्हें चाहिए कि वह हमारे दृष्टिकोण एवं हमारी स्थिति के बारे में प्रभावपूर्ण ढंग से परिचय दें।

आप अमरीका को ही लीजिये जिसने संकट के समय हमारी सहायता की परन्तु जब राष्ट्रपति कैनेडी की मृत्यु हुई तो हमारे प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंचे जब कि राष्ट्रपति डिगाल और अन्य बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित थे ।

प्रचार के बारे में जो कुछ कहा जाय कम है। पाकिस्तान के समाचारपत्र डान में यह खबर छपी है कि ढाका के आरकबिशप को, जिन्होंने ईसाई अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कहा था, इसलिए नहीं पकड़ा जा सका चूंकि वह अमरीका नागरिक थे, परन्तु हमारे प्रचार विभाग को कुछ खबर नहीं है। ट्यूनीशिया ने श्री बूरगिबा ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है। समझ में नहीं आता कि हमारे राजदूत वहां क्या कर रहे हैं। क्यों वह उन का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते ।

चूंकि पुराने भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी अफ्रीका में कठिनाईयों का सामना करने से हिचकिचाते हैं इसलिए हमें चाहिये कि वहां पर गतिशील युवक भेजे जायें।

विदेशी पत्रकारों की चर्चा की जाती है परन्तु उन को जो सुविधायें यहां उपलब्ध होनी चाहिएं वह उपलब्ध नहीं है। उन्हें बिजली और पानी तक की उचित सुविधा नहीं दी जाती ।

प्रचार विभाग वाले लोग ठीक तरह से काम नहीं करते। उनकी लापरवाही के कारण, जब नाईजीरिया का दल यहां पर आया, तो वह सूचना तथा प्रसारण मंत्री से नहीं मिल सका। श्री डी० ही० तहमंकर ने दक्खन हेरल्ड में बताया है कि हमारे प्रचार विभाग में किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं ।

मेरा यह सुझाव है कि हमारे देश की विदेश नीति, उसकी कार्यान्विति और उसका प्रचार, इन सब पक्षों को समूचे तौर पर लिया जाय। पूर्वी अफ्रीका में चीनियों ने अपने प्रभावपूर्ण प्रचार द्वारा ब्रिटिश प्रभाव को खदेड़ दिया है और अमरीका प्रभाव को भी खदेड़ दिया है। वह हमारे प्रभाव

को भी वहां पर निष्क्रय करना चाहते हैं। यदि उन का प्रचार पूर्वी अफ्रीका में इसी तरह होता रहा तो स्थिति बिगड़ जायेगी ।

Shri Bishanchander Seth (Etah) : I feel sorry for the method in which Shri Manoharan referred to the people of South who are there in Ceylon, and I must make it clear that no line can be drawn between the people who belong to the South and others.

Nobody was in favour of realasing Sheikh Abdullah. I had myself said at the top of my voice that if we released Sheikh Abdullah we would commit a blunder. Now he has been released and I can well imagine that a great danger is ahead for us due to his release. Today he is talking of self-determination. It seems our Government is slackening its attitude towards Kashmir. I want to make it clear that if our Government change its attitude regarding Kashmir, the dire consequences will follow.

Recently, our constitution was so amended as to check any attempt at disintegrating our country's territorial integrity. Today when Sheikh Abdullah and his colleagues are talking openly about disintegrating our territorial integrity, why no action is being taken against them ? Why are they not arrested under that law ? The fact of the matter is that there is a wide gap between profession and practice so far as our Government is concerned. The Government have already committed huge mistakes. If any wrong step is taken, now about Kashmir, that will lead to disintegration of the country. There is only one way out of the present situation. State of Emergency should be declared in Kashmir, The present Government of Kashmir should be suspended and President's rule should be enforced. Otherwise Kashmir will become a base of Americans.

A strange proposal has been put forth in the Home Minister'sConference. It has been said that the Pakistani infiltrants will not be sent back for two months. This proposal is against the wishes of the people. If the infiltrants do not go back in two months time they will never go back after that.

Although every Congress Member has praised the foreign policy that we pursue, in fact it has proved most ineffective. I want to give a few suggestions in regard to the foreign policy. We should break diplomatic relations with both China and Pakistan. All the trade transactions with Pakistan should be discontined. We should withdraw the Kashmir case from the Security Council. We have seen that this case is hanging fire for so many years and no useful purpose would be served by discussing the matter in the Security Council. We should also sever our relations with Commonwealth. And also we should stop pleading the case of China's admission in the U.N.O., The Government, should give recognition to Dalai Lama's Government in Tibet and help him to establish his rule there in Tibet once again. The Government have not been giving recognition to the Government of Israel because it want to appease the Mohammedans. This recognition should be given immediately.

I propose that both Pakistan and China should be given an ultimatum to either vacate our territories, upto 15th of May or be prepared for war. Pakistan is daily raiding our territories. killing our men and taking away cattle heads. It is mainly due to the weak policy pursued by us. Uness we relinquish the feeble. mentality and are prepared to face any danger, Pakistan and China will not come to their senses.

The condition of the Indians living in Burma, Ceylon and Pakistan is pitiable. All the properties of the Indians living in Burma have been snatched away but our Governmnt is unable to do any thing to improve their lot. If we are not able to defend the interests of our people living in a small country, like Burma, how can we be expected to take a stand against the bigger countries?

Much has been said about the competency of our missions abroad. But then what was the need for the Prime Minister to address special letters to Governments of all the countries of the world at the time of Chinese attack on India. This is a sad reflection on the state of affairs prevailing in our Embassies abroad. To protect our interests in foreign countries, it is essntial that only such persons should be sent as ambassadors there who can interpret our policies correctly and carry them out with firmness in those countries.

Government has expressed concern over the expulsion of 30,000 christians from Pakistan. But it has slept over the fact that today 4000 foreign missionaries have been engaged in the task of converting Hindus intoChristians and spending a lot of money for this purpose. This thing should be checked and they should be asked to leave this country immediately. Government should deal with the question of Kashmir with a firm hand and should arrive at a decision without any undue delay.

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : हमारी विदेश नीति का मूल तत्व यह है कि हम विश्व में शांति तथा विश्व के सब देशों से मित्रता बनाये रखने के पक्ष में हैं। हम तटस्थता की नीति के पक्ष में हैं, अर्थात हम गुटों से अलग रहना पसन्द करते हैं। और हमारी तटस्थता की नीति सफल रही है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश हमारे मित्र बन गये हैं। दूसरी ओर, चीन के समर्थक कम होते जा रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी तटस्थता की नीति तथा दूसरी नीतियां, जिनका हमने प्रभावशाली ढंग से पालन किया है, कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सकी है।

मैंने कुछ देशों का भ्रमण किया है और जहां भी मैं गया, मुझे वहां पर भारतीय लोगों से यह आम शिकायत सुनने को मिली कि विदेशों में हमारे दूतावासों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

उनका कहना है कि कई महीनों तक उनकी शिकायतों का उत्तर नहीं दिया जाता है। लन्दन में कुछ भारतीय नागरिकों ने मुझे बताया कि पारपत्र (पासपोर्ट) फिर से बनवाने में उन्हें ५/६ महीने लग जाते हैं। यह बहुत ही खेद की बात है। मंत्री महोदय को राजदूतावासों के प्रशासन को ठीक करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें सुनने को न मिलें। बर्मा सरकार ऐसी नीति पर चल रही है जिससे बर्मा में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बर्मा ने सारे कारबार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, जिससे भारतीय व्यापारी कारबार से वंचित हो गये हैं। अफ्रीका में रहने वाले भारतीय उदभव के व्यक्तियों के साथ हाल ही में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों द्वारा भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। वे बहुत पहले उन देशों में जा कर बस गये थे अतः यह

खेद का विषय है कि उन देशों द्वारा उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और हमारे दूतावासों को उनके प्रति अधिक सहानुभूति दिखानी चाहिये। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सम्बंध में सरकार को अपनी नीति और अधिक सक्रिय बनानी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जिससे भारत की शान पर धब्बा लगे, फिर भी वह उनकी कई प्रकार से सहायता कर सकती है। मेरा यह भी निवेदन है कि अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिक छात्रवृतियां दी जानी चाहियें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश के पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बंध होने चाहियें। यह दोनों देशों के हित की बात है। हम पिछले १७ वर्षों से पाकिस्तान को खुश करने की नीति का पालन करते रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान ने उसकी सराहना नहीं की है, अपितु चीन के साथ सांठगांठ कर ली है। अतः भारत को पाकिस्तान के प्रति कड़ी नीति अपनानी चाहिये। सिंधु जल संधि की कार्यान्विति से भारत को जो कठिनाईयां हो रही हैं, उनकी ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया जाना चाहिये।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति की समस्या प्रायः भुला दी गई है। हमें पाकिस्तान का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिखों के बहुत से तीर्थस्थान हैं। अतः हमें पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए जोर देना चाहिये कि भारत से जो लोग उन तीर्थ स्थानों को जायें, उन्हें वह पूरी सुविधायें उपलब्ध करें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The foreign policy of India has lost all its glamour. A feeling of shyness has overtaken it, because all the advantages, that the prestige of Mahatma Gandhi the great past of the country, its large population and strong armed forces had brought to it, have vanished. The reason is that India had not adopted a correct attitude towards the three leading countries of the world—America, Russia and China,—and did not try to understand them correctly.

China is suffering from a malady and has been committing these follies because she is quite ignorant of that malady and that malady is Marxism. She had adopted Marxism to remove inequality within her own country and between the various countries of the world. I have myself been suffering from this malady from the very beginning. There is great disparity prevailing among the 200 crores of coloured people on the one hand and 100 crores of white people of the world on the other. The Five principal disparities are : (1) inequality of production— because those countries have advanced techniques of production (2) inequality of prices—the prices of raw materials have not risen whereas the prices of the finished products are rising daily, (3) inequality of weapons of war, (4) inequality of skill, and (5) inequality of territory—because the white countries are sparsely populated whereas the other countries are densely populated. These disparities are eating away the world. There is disparity even between Russia and China who are both followers of Marxism. The reason is that Marxism has a remedy for inequalities inside a country but it has no remedy for international disparities. China is not happy about it. But in her pursuit, China has attacked only the weaker countries. I had expected that China and India would one day fight together against these international inequalities. I, therefore, warn the coloured people of the world to open their eyes to this communist menace, because the communists dare not fight against the whites, but the coloured nations of the world, who are very weak. China

is the demon of the modern world. She has become a spokesman of 200 crores of coloured people, though through wrong means.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

The Indian Government should not labour under this misunderstanding that it is merely a matter of propaganda. It is a conscientious issue. We should have to remove these five inequalities from the world first and these can be removed by the combined efforts of the whites and non-whites. The foreign policy of this country has failed because China has succeeded in assuming the leadership of the non-whites by taking up the question of these disparities. India and the other non-white countries have to strive to wrest this leadership from China. I do not say that we should attack China. China invaded India and still to keep diplomatic relations with her demonstrates in clear terms that our Government has not taken into its head this basic problem as yet.

The farmers of our foreign policy have been influenced by the leftist party of England, who have always adopted a dual attitude in international affairs. This is why we have only lip sympathy for Russia and have been purchasing our requirements from the Western Countries. We have not yet acquired the skill of deceiving other people which is the hall-mark of British foreign policy. In the absence of that skill, it is no use initiating the British people. We have been trying to be tactful for the last 17 years ; and the result is that we have achieved nothing, and on the other hand we have become inactive. The big, powerful countries can afford to follow this policy of tactfulness, because they have to solve important problems of the world. But newly emerged countr ies have to start anew, and if they run after these things, they cannot make any progress.

Unless we bring to the notice of the whole world those five international inequalities, we cannot advance a step further. By merely harping on our troubles, with either Pakistan or China, we cannot impress the people of the world because it would not lend that touch of universality. We cannot boast of idealism when we have to beg for food for our people. Our present foreign policy has therefore, failed to deliver the goods.

Our foreign policy should pinpoint its attention on the removal of imbalances in prices and on the removal of poverty. on an international level. We should try to live in cooperation with Russia and America and should not discriminate between these two powerful countries.

We have not raised our voice openly against the entry of the American 7th fleet in the Indian Ocean. We should be firm in our policy. We should have openly told America to do some thing for the world and for India in case the 7th fleet enters the Indian Ocean.

We should seriously reconsider about our present policy of non-alignment. I am also a supporter of the policy of a third force in international affairs. But this has been badly mutiliated by the External Affairs Ministry. Our policy of non-alignment is no more an impartial one. We should give up this policy and have some ideal before us to serve as a guide. Dependence on British Commonwealth and Afro-Asian countries and to consider ourselves non-aligned are three very undesirable things for India·

The foreign publicity division of the External Affairs Ministry sends out a bulletin to our embassies abroad. A copy of that bulletin should also be supplied to me.

We should say good-bye to English whether Hindi may take its place or not. Unless this is done, our foreign policy cannot be put in its right perspective.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा): विदेशों में भारत को गत शताब्दी में जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह हमारी विदेश नीति का ही परिणाम है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी विदेश नीति हमारी आन्तरिक नीति से बहुत अधिक मेल खाती है और उन मानवीय तथा सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप है जिनका भारत सदैव समर्थन करता आ रहा है। अतः यह कहना गलत है कि हमारी विदेश नीति यथार्थ नहीं है। भारत को अपनी तटस्थता की नीति नहीं छोड़नी चाहिये। इससे भारत के सम्मान को धक्का ही नहीं लगेगा अपितु पूर्ण निरस्त्रीकरण तथा विश्वशांति की संभावनायें समाप्त हो जायेंगी। यह नीति चीनी आक्रमण जैसे बुरे समय में भी सफल सिद्ध हुई है और ऐसे राष्ट्रों ने, जो विभिन्न गुटों से सम्बन्धित हैं, न केवल इस नीति की सराहना की है, अपि उन्होंनेतु हमें सहायता भी दी है।

हमारी तटस्थता की नीति ने साम्यवादी तथा पूंजीवादी देशों पर काफी नैतिक तथा राजनीतिक प्रभाव डाला है। और उन्हें काफी उदार बना दिया है। यह इसी नीति का प्रभाव है कि टैस्ट बैन संधि एक वास्तविकता बन गई है। जिन देशों में साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा तानाशाही का बोलबाला है, वे कभी भारत से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नीति उनसे मेल नहीं खाती है। हमें ऐसे देशों की परवाह भी नहीं करनी चाहिये।

जकार्ता सम्मेलन में भाग लेने से अपने निर्णय से भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह शांति बनाये रखने के लिये वचनबद्ध है। कोलम्बो प्रस्तावों तथा चीन के प्रति हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह बिल्कुल सही है। आशा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चीन से अपना राज्यक्षेत्र खाली कराने में सफल हो जायेंगे। हमारी राजनीति शांति तथा सामाजिक न्याय पर आधारित है और भविष्य में भी ऐसी ही बनी रहेगी। एशिया के देशों में एकता बनाये रखना बहुत जरूरी है। यदि भारत या किसी अन्य देश द्वारा एशिया यूनिटी लीग जैसे किसी संगठन का प्रस्ताव रखा जाये, तो बहुत अच्छा होगा।

हमारी विदेश नीति में सब से बड़ी कमजोरी हमारा प्रचार है। अतः हमें और अधिक पुस्तिकायें निकालनी चाहियें और अपने दूतावासों को सुदृढ़ करना चाहिये ताकि न केवल विदेशों के ठीक समाचारों का हमें पता लग सके अपितु हमारा सही दृष्टिकोण भी उन देशों के सामने रखा जा सका। विदेशी प्रचार विभाग में भी आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। हमारे दूतावासों में असैनिक पदाधिकारियों की भरमार है। स्पष्ट विचार-धारा वाले व्यक्तियों को, जिन्हें राजनीति तथा प्रशासन का अनुभव हो, राजदूतों के तौर पर विदेशों में भेजा जाना चाहिये।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में विदेश नीति के आयोजन के बारे में कोई उल्लेख होना चाहिये। विदेशी मामलों के बारे में एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिये, जो विदेश नीति की समस्याओं पर सरकार को सलाह दे सके।

मैं आश्चर्यचकित हूं कि कश्मीर के मामले में इतना आवेश क्यों फैला हुआ है। एक तो क्यों सैंकड़ों लोग भी पथभ्रष्ट हो जाए तब भी कोई हानि नहीं हो सकती। हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे है उससे पाकिस्तान और भारत दोनों को हानि पहुंच रही है। अरब के इसलामी राष्ट्रों को पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिये कि वह अपनी नीति को बदले। भूतकाल में विश्व को भय की भावना में ग्रस्त होने पर घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा है और मैं आशा करती हूं कि अब हमें वैसी विपत्ति का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

विना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : प्रधान मंत्री वाद-विवाद का उत्तर सोमवार को देंगे। मैं इस समय कुछ एक बातों का उत्तर देना चाहता हूं।

नागालैंड में गैर सरकारी लोगों की एक सभा हुई थी जिसमें यह संकल्प पारित किया गया था कि नागालैंड की सरकार विद्रोही नागाओं से मिलकर कोई निबटारा करे और शान्ति की स्थापना करें। संकल्प में श्री जयप्रकाश नारायण, श्री चालिहा, श्री शंकर राव देव और माइकेल स्काट का उल्लेख किया गया था। उसके बाद वहां विधान सभा में भी एकमत से एक संकल्प पारित किया गया था कि शान्ति स्थापना के लिए बातचीत की जाए। श्री शंकर राव देव तो बीमार है। किन्तु श्री जय प्रकाश नारायण और श्री चालिहा से इसके लिए आग्रह किया गया है। श्री माइकेल स्काट भी यहां पहुंच चुके हैं। हमने श्री स्काट को यह बता दिया था कि नागालैंड की जो स्थिति इस समय है अर्थात वह भारत का एक राज्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा क्योंकि आशंका थी कि श्री स्काट स्वतंत्र नागालैंड चाहते हैं। अब विद्रोहियों के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्से बातचीत करनी है।

मैं इस प्रयत्न का स्वागत करता हूं क्योंकि अब नागालैंड के विद्रोहियों को अनुभव करना चाहिये कि इस बात को सहन नहीं किया जा सकता कि देश के किसी भाग के लोग विदेशों से शस्त्रास्त्र और प्रशिक्षण प्राप्त करके देश के प्रति विद्रोहपूर्ण कार्यवाहियां करें।

हम वहां कुछ विकास कार्य करना चाहते है किन्तु ऐसी तनाव की स्थिति में कुछ नहीं हो सकता और उससे लोगों और सरकार दोनों को हानि होती है। अतः यह नागा लोगों और विशेषतः विद्रोही नागाओं के हित में है कि वे इस सुअवसर से लाभ उठा कर शान्ति स्थापित करें। जो विद्रोही नागा अपने छिपने के स्थानों से बाहर आकर वार्ता में भाग लेना चाहें उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिये ताकि बातचीत के लिये अच्छा वातावरण पैदा हो।

नेफा में बहुत विकास कार्य हो रहा है। पिछले ७ या ८ मास में शिक्षा, सड़कें, अस्पतालों के सम्बंध में वहां अच्छा रचनात्मक कार्य हुआ है हम चाहते हैं कि वहां के

प्रतिनिधि इन कामों में भाग लें और नेफा का लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण भी हो। दुर्गम पहाड़ों से घिरे इस क्षेत्र में छोटे छोटे स्वायत्तशासी निकाय बनाने की आवश्यकता है अतः असम के राज्यपाल कुछ दिनों में इस कार्य के लिए एक समिति स्थापित करने वाले है। चीन के आक्रमण से पूर्व जहां जहां प्रशासनिक निकाय थे वे स्थापित किये जा चुके हैं।

गोआ के विलय के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यदि गोआ अभी संघीय राज्य क्षेत्र बना रहे तो इससे गोआ को बहुत लाभ होगा क्योंकि केन्द्र उसके विकास के लिए पर्याप्त सहायता देता रहेगा।

श्री नाथपाई (राजापुर) : यह उसके किसी राज्य में विलय होने पर भी केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हो सकता है किन्तु उस उत्तरदायित्व का कुछ भार उस राज्य को उठाना पड़ता है। वहां के वर्तमान मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि वहां की यही स्थिति दस साल तक रखी जाए।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री के परामर्श देने पर उन्होंने कहा था कि वह इस आशा से भारत सरकार का परामर्श स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आखिर गोआ के लोगों की इच्छा का पालन किया जाएगा। उन्होंने दो वर्ष की बात कही थी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यहां मैसूर और महाराष्ट्र के सदस्य उपस्थित है और मैं चाहता हूं कि बाहर भी इसी प्रकार की सद्भावना दिखाएं और विलय के प्रश्न को मैसूर और महाराष्ट्र उपयुक्त समय पर हल कर लेंगे।

श्री नाथ पाई : मैं ने तो यह प्रश्न उठाया था कि गोआ वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन कैसे आता है? मुझे आशंका है कि श्री शास्त्री अपनी प्रकृति के प्रतिकूल एक शरारत पैदा कर रहे हैं।

श्री शास्त्री : मैं उतना भोला नहीं जितना लगता हूं किन्तु श्री नाथ पाई का आरोप इस समय अनुचित है। पांडीचेरी और गोआ को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के सम्बन्ध में मैं श्री नाथपाई से सहमत हूं किन्तु पांडीचेरी से यह आपत्ति प्राप्त हुई है कि उसकी स्थिति यही रहने दी जाए।

श्री पु० र० पटेल : दादरा और नगरहवेली के प्रशासन में हाल ही में क्यों परिवर्तन किया गया है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वहां के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु उन्हें गोआ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया है क्योंकि वहां वरिष्ठ अधिकारी की आवश्यकता थी। वहां के लोगों में ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि हम कोई कार्य उनकी इच्छा के प्रतिकूल करेंगे।

श्री नाथ पाई और श्री स्वैल ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में कोई भी हमारा मित्र नहीं है किन्तु यह सच नहीं है। नेपाल के साथ कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी जो दूर हो चुकी है। दो वर्ष से उसके साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। डा० राधा कृष्णन द्वारा वहां के दौरे का

बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। नेपाल के महाराजा और महारानी का यहां भव्य स्वागत हुआ था। वैदेशिक व्यापार मंत्री और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री भी वहां का दौरा कर आये हैं। वहां भारत की सहायता से और नागरिकों के संयुक्त उपक्रम द्वारा कुछ उद्योग भी स्थापित किये जा रहे हैं। वहां हमारी परियोजनाएं भी प्रगति कर रही हैं।

बर्मा कुछ मामले में अलग थलग रहा है। वे न तो गुटविहीन राष्ट्रों के तैयारी सम्मेलन में सम्मिलित हुए और न ही जकार्ता में उनका कोई प्रतिनिधि गया। किन्तु बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं हमारे राष्ट्रपति ने बर्मा के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। मिलकर बातचीत करने से बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी।

श्रीलंका में राज्य विहीन भारतीय लोगों की समस्या है जो ऐसी नहीं कि हल न हो सके हम उस का कुछ हल निकालेंगे जो निस्संदेह श्रीलंका की सरकार की सहायता से ही किया जा सकता है और हमें सहायता मिलने की आशा है। हम पुनः इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेंगे ।

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पड़ौसी देशों से हमारे सम्बन्ध असंतोषजनक नहीं हैं और इस सम्बन्ध में निराश नहीं होना चाहिये।

Shri Ram Manohar Lohia : Name any of the neighbourers who is more friendly towards us them towards China.

Shri Lal Bahadur Shastri : You might have seen the Communique issued by the President of Iraq. मैं इस बात को नहीं लेता। यह आवश्यक नहीं कि वे देश निश्चित शब्दों में ही मित्रता का दम भरें उन्हें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है।

हमें बहुत दुःख है कि भूतान के प्रधान मंत्री मारे गये हैं किन्तु इस बात ही प्रसन्नता है कि भूतान के राजा वहां पहुंच गये हैं। वे बहुत लोक प्रिय हैं और वे अवश्य राज्य में शान्ति स्थापित कर देंगे। भूतान और सिक्कम के साथ हमारे सम्बन्ध वैसे ही बने रहेंगे।

गुटविहीन देशों का सम्मेलन अक्तूबर में काहिरा में होगा। कोलम्बो में तैयारी सम्मेलन में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है और हमारे कार्य को बहुत प्रशंसा की गई है।

जकार्ता सम्मेलन हो रहा है। डा० लोहिया का अनुरोध है कि हमें उसमें शामिल नही होना चाहिये क्योंकि वहां चीनी प्रतिनिधि होंगे।

श्री रंगा : यह राष्ट्र का अपमान है।

Shri Ram Manohar Lohia : Is it proper that they should have relations with China.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस बात को दोहराता हूं कि भारत का उसमें शामिल होना बहुत आवश्यक है।

श्री नाथ पाई : आपने आखरी सप्ताह तक इस बारे में क्यों निर्णय नहीं किया था। आपने अकस्मात सरदार स्वर्ण सिंह को भेजने का निश्चय किया और संवाददाताओं को इतनी जल्दी में भेज दिया कि वे स्वास्थ्य पत्र भी प्राप्त न कर सके।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को ठीक जानकारी नहीं। हमने प्रारम्भ में ही कहा था कि इस सम्मेलन का विचार बुरा नहीं यद्यपि गुटविहीन राष्ट्रों के सम्मेलन का अधिक महत्व है।

हमने यह निर्णय ठीक ही किया है। हमें तैयारी सम्मेलन की चर्चाओं से घबराना नहीं चाहिये।

अरब राष्ट्रों में हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं संयुक्त अरब गणराज्य और ईराक। ईरान के राष्ट्रपति के हाल के दौरे में जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया था वह सराहनीय है और इराक के समाचारपत्रों में श्री आरिफ के अतिथ्य की जो भारत में उन्हें प्राप्त हुआ भूरी भूरी प्रशंसा की गई है।

शेख अब्दुल्ला के रिहा करने का निर्णय ठीक था। हम जानते थे इसमें कुछ खतरा है किन्तु मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जिस प्रकार गांधी जी जेल के बाद सारी स्थिति की जानकरी प्राप्त किये बिना कोई वक्तव्य नहीं दिया करते थे उसी तरह शेख अब्दुल्ला को चाहिये था किन्तु उसने उसके बिना ही वक्तव्य दे दिये हैं।

शेख अब्दुल्ला को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता है किन्तु कोई भी सरकार इस प्रकार का प्रचार सहन नहीं कर सकती कि देश के किसी भाग को स्वतन्त्र करने या अलग करने का प्रचार किया जाये।

सुरक्षा परिषद् की बैठक ५ मई को हो रही है। श्री चागला भारत की स्थिति को स्पष्ट बता चुके हैं कि काश्मीर का विलय अपरिवर्तनीय है। आशा है और जटिलताएं पैदा नहीं होंगी और शेख अब्दुल्ला चर्चा किये बिना कोई निर्णय नहीं बना लेंगे। कोई कठिन स्थिति पैदा हुई तो सरकार उसके लिये तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

[इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४ / २४ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 13th April 1964/Chaitra 24, 1886 (Saka)]

GMGIPND—LS III—572 (Ai) LS—27-6-64—600.